@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, गुरुवार, 2 अप्रैल 2026, वर्ष-1, अंक-144, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

सामंथा ने शेयर किया अपना 'पावर मॉर्निंग' रूटीन

...पेज 8

ईरान जंग के बाद नाटो से अलग हो सकता है अमेरिका

ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ उनके अभियान में साथ नहीं दिया

वाशिंगटन, एजेंसी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो से हटने पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूरोपीय साथियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान संघर्ष के बाद यूएस इस गठबंधन पर फिर से समीक्षा कर सकता है।

रूबियो ने नाटो की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सहयोगी देश अमेरिकी सैन्य अभियानों में बाधा डालते हैं, तो इस गठबंधन का महत्व कम हो जाता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, अगर नाटो सिर्फ यूरोप की रक्षा के लिए है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें सैन्य अड्डों का उपयोग नहीं करने देता, तो यह एकतरफा व्यवस्था बन जाती है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश दैनिक द टेलिग्राफ को दिए इंटरव्यू में गठबंधन को पेपर टाइगर बताया और कहा कि इससे बाहर निकलना सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि गंभीर विचार का विषय है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ उनके अभियान में साथ नहीं दिया।

विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की नाराजगी सामने आई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अहम मार्ग है, लेकिन इसके बावजूद सहयोगी देशों ने नौसैनिक बल तैनात करने में हिचक दिखाई, जिससे वॉशिंगटन में असंतोष बढ़ा।

अमेरिकी प्रशासन ने इस विवाद को ईरान संघर्ष के व्यापक संदर्भ में रखा है। रूबियो के अनुसार, अमेरिकी सेना अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब है और ईरान की वायुसेना, नौसेना, मिसाइल सिस्टम और रक्षा ढांचे को काफी हद तक कमजोर किया जा चुका है। उन्होंने कहा, हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बहुत करीब हैं, और यह अभियान ईरान के लिए निकट भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करना लगभग असंभव बना देगा।

हालांकि, यूरोपीय नेताओं ने इस रुख का विरोध किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने नाटो को दुनिया का सबसे प्रभावी सैन्य गठबंधन बताते हुए इसका समर्थन दोहराया और स्पष्ट किया कि ब्रिटेन ईरान संघर्ष में शामिल नहीं होगा।

1949 में स्थापित नाटो लंबे समय से अमेरिका और यूरोप के बीच सुरक्षा सहयोग का आधार रहा है। ये संगठन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन मौजूदा हालात में यह सिद्धांत केवल सदस्य देशों पर हमले की स्थिति में लागू होता है, न कि ईरान जैसे बाहरी संघर्षों पर। ऐसे में ट्रंप के बयान ट्रांस-अटलांटिक रिश्तों में बढ़ती दरार को और गहरा कर रहे हैं।

होर्मुज स्ट्रेट खुलने तक समझौता नहीं : ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से संघर्ष विराम को लेकर बड़ा दावा किया है। 'नए शासन के राष्ट्रपति' की गुजारिश और 'सीजफायर' की शर्त को लेकर एक बार फिर अपने ट्रुथ सोशल पर बयान दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति से कम कट्टर और कहीं ज्यादा समझदार ईरान के नए शासन (न्यू रिजिम) के राष्ट्रपति ने अभी-अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए कहा है!

ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में शर्त की बात करते हुए आगे लिखा, इस बारे में हम तब सोचेंगे जब होर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, वो ज्यादा सुरक्षित होगा। तब तक हमारी ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी और तबाह होते रहेंगे। जैसा कि वे कहते भी हैं, वापस स्टोन एज में ले जा रहे हैं!!! अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो किस 'न्यू रिजिम' की बात कर रहे हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में, कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबाफ के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, हालांकि उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है।

जन विश्वास विधेयक 2026 लोकसभा में पारित

नई दिल्ली,एजेंसी। लोकसभा में बुधवार को एक हजार से अधिक कानूनों का सरलीकरण करने और छोटे-मोटे मामलों में अदालती चक्कर से लोगों को बचाने के प्रावधान वाला जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस की के काव्या के विधेयक में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप जनता पर विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनों का सरलीकरण करने के वास्ते यह विधेयक लायी है।

वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 195 रुपये महंगा

नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बीच तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी-भरकम बढ़ोतरी की घोषणा की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली अप्रैल से 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 2,078.50 रुपये का मिलेगा। इसकी कीमत गत 07 मार्च को बढ़ाकर 1,883 रुपये की गयी थी। इस प्रकार अब यह 195 रुपये यानी 10.38 प्रतिशत महंगा हो गया है। इस साल एक जनवरी से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में यह पांचवीं बढ़ोतरी है। इस दौरान दिल्ली में यह 498 रुपये महंगा हो चुका है।

घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 07 मार्च को 60 रुपये की वृद्धि की गयी थी और फिलहाल दिल्ली में इसकी कीमत 913 रुपये प्रति सिलेंडर है।

डिजिटल भुगतान के लिए दो स्तरीय सत्यापन जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

ऑनलाइन भुगतान में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई समेत सभी डिजिटल मंचों से होने वाले लेनदेन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण बुधवार से अनिवार्य हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के तहत सभी तरह के डिजिटल लेनदेन के लिए अब दो-स्तरीय सत्यापन करना अनिवार्य हो गया है।

नए नियम के तहत कोई भी डिजिटल लेनदेन पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता का दो स्तरों पर सत्यापन करना होगा। इसका मतलब है कि अब केवल यूपीआई पिन डालने से ही भुगतान पूरा नहीं होगा बल्कि ओटीपी, अंगुली के निशान या चेहरे का सत्यापन जैसे कदम भी जरूरी होंगे। इस तरह यूपीआई पिन लीक होने की स्थिति में भी अनधिकृत भुगतान को रोका जा सकेगा।

आरबीआई ने कहा है कि सभी डिजिटल भुगतान लेनदेन में दो-स्तरीय सत्यापन करना अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए किसी विशेष तरीके को अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन अधिकांश मामलों में एसएमएस के जरिये आने वाले 'वनटाइम पासवर्ड' (ओटीपी) का अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने अपने निर्देश में कहा था कि बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाओं समेत सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और प्रतिभागियों को एक अप्रैल, 2026 तक इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। नए प्रावधानों के तहत बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट लेने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह कदम उपयोगकर्ता को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के मकसद से उठाया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू होने से डिजिटल लेनदेन में कुछ सेकंड की देरी हो सकती है, क्योंकि उपयोगकर्ता को अतिरिक्त ओटीपी या अन्य सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा और भरोसा बढ़ने की उम्मीद है।

सार समाचार

अशोक खरात 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

नासिक,एजेंसी। नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खरात को आज नासिक जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी.एन. इचपुरानी की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण और धोखाधड़ी के लिए 10 प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं और फोन पर उसके खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गयी हैं। फिलहाल एसआईटी उससे संबंधित मामलों की जांच कर रही है। एसआईटी ने आज ही उसके बेटे हर्षवर्धन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

गांदरबल मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

श्रीनगर,एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरक्षा बलों ने कल रात से जारी मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। सेना ने बुधवार को यह जानकारी दी। सेना के अनुसार यह आतंकवादी गांदरबल के अराहामा इलाके में मंगलवार शाम को शुरू किए गए एक अभियान के दौरान मारा गया। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पर बताया, 31 मार्च की रात को, रुक-रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच घेराबंदी को रणनीतिक रूप से फिर से व्यवस्थित किया गया। हमारे जवानों ने प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी मारा गया। अभियान अभी भी जारी है।

प्रियंका ने हेमंत बिस्वा सरकार पर साधा निशाना

गुवाहाटी,एजेंसी। कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य की सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाये। नजीरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमती वाड्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई असम की संस्कृति, अभिव्यक्ति और जनता की ताकत को बचाने की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के नाम पर लोगों, खासकर महिलाओं, को डराया और दबाव में रखा जा रहा है।

अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का विधेयक लोकसभा से पारित

नई दिल्ली, एजेंसी।

अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने संबंधी 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। वहीं, आंध्रप्रदेश में विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

कांग्रेस सदस्य मनिकम टेगौर ने लोकसभा में 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026' पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही यह मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश के विकास और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वाईएसआरसीपी के सदस्य पीवी मिधुन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 34,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी और प्रभावित लोगों को मुफ्त विकसित भूखंड, आवास योजना और उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया था। लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया।

मणिपुर के उखरुल, कामजोंग जिलों में बरकरार है तनाव

इंफाल,एजेंसी। मणिपुर के उखरुल और कामजोंग जिलों में विभिन्न झड़पों के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन घटनाओं में इंफाल-उखरुल सड़क पर कुकी और तांगखुल नागा समुदायों के बीच हुई झड़पें शामिल हैं, और यह तनाव तब और बढ़ गया जब कथित तौर पर इसी समुदाय के एक अन्य कट्टरपंथी समूह ने चार नागा उग्रवादियों की हत्या कर दी।

उखरुल और कामजोंग में मुख्य रूप से तांगखुल लोग रहते हैं। इन दोनों जिलों में कुछ कुकी गाँव भी हैं। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष के कारण राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों का अपहरण भी हुआ है।

तांगखुल समुदाय के लोगों को इंफाल पहुँचने के लिए एक लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है।

विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान 'जनगणना 2007' शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी।

विश्व के सबसे बड़े जनगणना अभियान 'जनगणना-2027' के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की बुधवार से शुरुआत हो गयी। यह पूरी तरह डिजिटल डेटा कैप्चर के साथ स्व-गणना की सुविधा वाली भारत की पहली जनगणना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु , उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनगणना 2027 के लिए आज यहां 'स्व-गणना' पहल में भाग लिया और अपने अपने आवास संबंधी जानकारी दर्ज की। श्रीमती मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जनगणना 2027 के लिए सरकार की 'स्व-गणना' पहल में भाग लिया।

राष्ट्रपति ने गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पोर्टल पर अपने आवास का विवरण स्वयं दर्ज किया। राधाकृष्णन और श्री मोदी ने भी अपने आवासों पर अपने अपने विवरण दर्ज किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए फॉर्म में विवरण दर्ज करने के फोटो भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने अपनी स्व-गणना पूरी कर ली है। आज जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो मकानों की सूची बनाने और आवास संबंधी कार्यों से जुड़ा है।

यह पहली बार है जब जनगणना के लिए डेटा संग्रह डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है। यह भारत के लोगों को अपने घर-परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करने का अधिकार भी देता है। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि वे अपने घर-परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करें और जनगणना की प्रक्रिया में भाग लें। जनगणना की इस राष्ट्रीय प्रक्रिया में जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की।

प्रारंभिक चरण में आज से स्व-गणना प्रक्रिया 08 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और राजधानी दिल्ली के नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद एवं दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र शामिल हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार पहले दिन इन स्थानों से लगभग 55,000 परिवारों ने पहले ही दिन इस सुविधा का लाभ उठाया।

स्व-गणना एक सुरक्षित और वेब आधारित सुविधा है, जो 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। पहली बार उत्तरदाताओं को प्रगणकों के आने से पहले अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन विवरण भरने का विकल्प उपलब्ध है।

बंगाल मतदाता सूची विवाद: दावों का निपटारा सात अप्रैल तक होगा: सुप्रीम कोर्ट

बंगाल में मतदाता सूची संशोधन प्रकिया संतोषजनक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन और तार्किक विसंगति के कारण हटाए गए नामों के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों में से 47 लाख का निपटारा 31 मार्च की शाम तक कर लिया गया है, और शेष 13 लाख मामलों का फैसला सात अप्रैल तक कर दिया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ कर रही है। न्यायालय को बताया गया कि लगभग 700 न्यायिक अधिकारी (जिसमें पश्चिम बंगाल के 500 और ओडिशा व झारखंड के 200 अधिकारी शामिल हैं) प्रतिदिन लगभग दो लाख मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। दावों और आपत्तियों पर आने वाले फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं।

इनकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर इन न्यायाधीशों के लिए आयोजित 'ओरिएंटेशन प्रोग्राम' पर आपत्ति जताई तो इस पर न्यायमूर्ति बागची ने इसे खारिज करते हुए कहा कि चूंकि न्यायाधीश अपने नियमित न्यायिक कार्य से अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए यह प्रक्रिया उचित है।

न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को वर्तमान चुनाव में तुरंत वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। वोट देने की पात्रता चुनाव आयोग द्वारा तय की गई पात्रता तिथि पर निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने बताया कि तार्किक विसंगति सूची के 60 लाख नामों में से अब तक लगभग 55 प्रतिशत को शामिल कर लिया गया है, जबकि 45 प्रतिशत को बाहर रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा कि दावों का निपटारा करने वाले अधिकारियों और अपीलीय न्यायाधिकरणों, दोनों को अपने आदेशों में स्पष्ट कारण दर्ज करने होंगे और मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया अपने तार्किक अंत तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक मताधिकार से अनिश्चित काल तक वंचित नहीं रखा जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी छह अप्रैल को होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति के साथ की बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार शाम मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, श्री मोदी ने सीसीएस के सदस्यों के साथ आवश्यक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी एवं एलएनजी की आपूर्ति में विविधता लाने, ईंधन शुल्क में कमी लाने और विद्युत क्षेत्र से जुड़े उपायों की समीक्षा की।

बैठक को बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिर कीमतों को सुनिश्चित करने और जमाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर बातचीत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचना एवं अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी का समय पर एवं सुचारू पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोयले के भंडार मौजूद है जो आने वाले महीनों में बिजली की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी होगी।

सरकारी स्कूलों में हवन के साथ नया सत्र शुरू

विद्यार्थियों का माला पहनाकर स्वागत किया, अभिभावकों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

फरीदाबाद,एजेंसी।

स्मार्ट सिटी के सरकारी स्कूलों में बुधवार से नए शैक्षणिक सत्र के तहत प्रवेश उत्सव की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर स्कूलों में पारंपरिक तरीके से हवन का आयोजन कर सत्र का शुभारंभ किया गया। इसके बाद नए रजिस्टर में विद्यार्थियों के नाम दर्ज कर उन्हें अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया गया।इस दौरान एक ओर जहां बच्चों का स्वागत माला पहनाकर उत्साहपूर्वक किया गया। वहीं, दूसरी ओर नई किताबों की जगह पुरानी पुस्तकें मिलने से कई छात्रों को निराशा का सामना भी करना पड़ा। पहले दिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, जिसके चलते नियमित पढ़ाई का माहौल पूरी तरह नहीं बन सका।

अध्यापकों ने बच्चों का परिचय लिया और उन्हें नए सत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ पढ़ाई भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। गांव डीग स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक समर देशवाल की अध्यक्षता में उपजिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह, सुभाष चौधरी, आनंदपाल राठी, उदयवीर गिल, तेजपाल यादव, धर्मवीर नंबरदार, रणजीत थानेदार ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।

अभिभावकों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईऐतमादपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक और प्रवेश उत्सव मनाया गया। स्कूल के मुख्य शिक्षक चतर सिंह ने बताया कि पीटीएम में अभिभावकों की फ्लावर दौड़, म्यूजिकल चेयर सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें अभिभावकों ने भाग लिया। अभिभावकों ने शिक्षकों के पास जाकर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरे, इसके पश्चात स्कूल के सभी बच्चों का रिजल्ट मुख्य शिक्षक द्वारा घोषित किया गया।

पुरानी किताबों से पढ़ाई पर उठे सवालप्रवेश उत्सव के दौरान सबसे बड़ी समस्या नई किताबों की अनुपलब्धता को लेकर सामने आई। कई स्कूलों में विद्यार्थियों को नई पुस्तकों के बजाय पुरानी किताबें वितरित की गईं। इससे बच्चों और अभिभावकों में निराशा देखने को मिली। अभिभावकों का कहना है कि हर साल सरकार द्वारा नई किताबें देने का दावा किया जाता है, लेकिन सत्र की शुरुआत में ही इस तरह की स्थिति चिंताजनक है। उनका मानना है कि नई किताबों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल में नई पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया पिछले वर्ष नवंबर में शुरू कर दी थी, लेकिन पुस्तकें अभी तक नहीं पहुंची। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई किताबों की आपूर्ति जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी और सभी विद्यार्थियों को नई पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल, पढ़ाई को बाधित होने से बचाने के लिए पुरानी किताबों का सहारा लिया जा रहा है।

प्रवेश बढ़ाने के लिए घर-घर अभियानस्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत अध्यापक और स्कूल स्टाफ घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है। इसके अलावा स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर स्कूल की उपलब्धियों से संबंधित बोर्ड लगाएं।

इन बोर्डों के माध्यम से स्कूल की शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि अभिभावक प्रभावित होकर अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं।सरकारी सुविधाओं का किया जा रहा प्रचारशिक्षा विभाग ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। इनमें छात्रवृत्ति, मुफ्त स्कूल ड्रेस, बैग, मिड-डे मील, पौष्टिक दूध सहित अन्य सुविधाओं का उल्लेख बोर्ड पर करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य अभिभावकों को यह बताना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

10 अप्रैल से होगी प्राइवेट खेल नर्सरियां संचालित

गुरुग्राम,एजेंसी।

नए सत्र के तहत बुधवार से जिले में 20 खेल नर्सरियां विधिवत रूप से शुरू की गई हैं। दो दिनों तक चले ट्रायल के बाद चयनित 500 खिलाड़ी अब खेल के मैदानों में पसीना बहाएंगे व प्रशिक्षकों की देखरेख में अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। नए सत्र की इन नर्सरियों के लिए हाल ही में दो दिवसीय ट्रायल आयोजित किए गए थे। हर एक खेल नर्सरी के लिए 25-25 बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है। इससे जिलाभर में 500 खिलाड़ियों की पौध तैयार की जाएगी। वहीं, निजी नर्सरियों की लिस्ट अभी तक मुख्यालय से स्वीकृत नहीं हुई है। जिस कारण इन नर्सरियों के 10 अप्रैल के बाद ही संचालित होने की संभावना है।

सरकारी नर्सरियों में क्रिकेट, जिमनास्टिक, तैराकी, मुक्केबाजी, बास्केटबाल, तायक्वांडो, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, कुश्ती, हैंडबॉल, फुटबॉल, जूडो और बैडमिंटन जैसे प्रमुख खेल शामिल है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप आठ से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लिए 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। खेल नर्सरियों का संचालन नेहरू स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सोहना स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम (मऊ पटौदी), खंडेवला स्टेडियम, भांगरौला, नखरौला, दौलताबाद (पवन पुत्र व्यायामशाला), धनवापुर (अजीत स्टेडियम) और न्यू कॉलोनी स्थित बैडमिंटन हॉल में किया जाएगा।

मानसून से पहले जल संरक्षण की तैयारी, बनेंगे नए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

गुरुग्राम,एजेंसी।

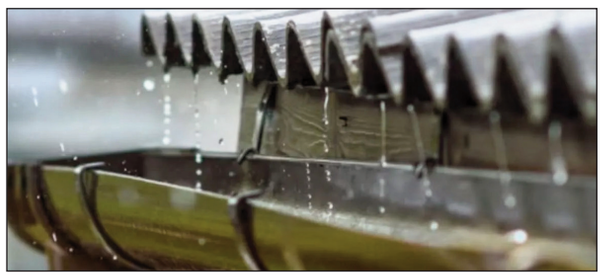

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त व सचिव अशोक कुमार मीणा ने बुधवार को गुरुग्राम पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों शहर राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री इन शहरों पर खुद नजर रखते हैं। वह समय-समय पर विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मास्टर ड्रेन, सर्फेस ड्रेन व सीवरेज नेटवर्क की समय रहते सफाई और मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए।

जहां दीर्घकालिक परियोजनाएं मानसून से पहले पूरी नहीं हो सकतीं, वहां अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि जल निकासी बाधित न हो। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सार्वजनिक स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जा सकें। इससे जलभराव की समस्या कम होगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। बैठक में ग्रीन बेल्ट को नीचा करने, चैनल की डी-सिल्टिंग, तालाबों की गहराई बढ़ाने (पौंड डीपनिंग), अतिरिक्त रोड गल्ली का निर्माण तथा बागवानी कचरे के नियमित उठान जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से जुड़े मुद्दों को भी सुना गया और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिया गया।

बैठक में पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, बजट घोषणाएं, जनसंवाद और सीएम घोषणाओं सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा कई आईटी आधारित नवाचार किए गए हैं, जिनमें स्मार्ट सिटी यूनिफाइड पोर्टल, वाटर एवं सीवरेज कनेक्शन पोर्टल, इंस्पेक्शन एप और सेनिटेशन एप शामिल हैं। इन पहलों की आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने सराहना की और इन्हें अन्य शहरों में भी लागू करने की बात कही। अंत में उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रकार की समीक्षा बैठक अब प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी, ताकि विकास कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित हो सके। बैठक में जीएमडीए सीईओ पीसी मीणा, फरीदाबाद निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, गुरुग्राम अतिरिक्त निगमायुक्त अंकिता चौधरी, यश जालुका व रविन्द्र यादव, फरीदाबाद अतिरिक्त निगमायुक्त सलोनी शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

डेढ़ करोड़ की ठगी में आरोपी पकड़ से दूर

पलवल,एजेंसी।

ऑनलाइन ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश के नाम पर एक करोड़ 65 लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अतवा निवासी ताहिर हुसैन ने बताया था कि वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सेल्समैन के तौर पर कार्यरत हैं। वह पहले ग्रो एप के माध्यम से शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता था। 13 फरवरी 2026 को उसने इंस्टाग्राम पर एक लिंक पर क्लिक किया था, जिसके बाद शालिनी कुलकर्णी नामक एक महिला ने व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया था। महिला ने ताहिर को बेहतर मुनाफे का लालच देकर एक ट्रेडिंग एप डाउनलोड करवाई और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। इस ग्रुप में मौजूद अन्य सदस्यों ने फर्जी तरीके से मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा कर उनका विश्वास जीता।

वाहन चोर गिरफ्तार, पांच बाइक बरामद

पलवल,एजेंसी।

हथीन की पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को पकड़ा है। इनके कब्जे से दिल्ली और हरियाणा से चोरी की गई पांच बाइक बरामद हुई हैं। दोनों आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदातों में सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आरोपी जावेद निवासी घिण्डा को हथीन बाईपास मानपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई, जो अक्तूबर 2025 में नगला अहसानपुर निवासी आसिफ के घर के बाहर से चोरी हुई थी।

पूछताछ में जावेद ने अपने साथी मुबारक निवासी जमालगढ़ का नाम बताया। उसकी निशानदेही पर एक अन्य बाइक भी बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने मुबारक को कोट रोड से गिरफ्तार किया। मुबारक की निशानदेही पर दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्रों से चोरी की गई तीन और बाइक बरामद की गईं।

प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर चालान

गुरुग्राम,एजेंसी।

शहर में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, इसके बावजूद कुछ लोग और दुकानदार नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए बुधवार को नगर निगम की टीम ने सेक्टर-57 इलाके में सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर खुलेआम प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल होते पाए जाने पर निगम की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर ही 10 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया। नगर निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल शहर में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह चेकिंग अभियान आगे भी लगातार इसी तरह से जारी रहेगा।

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन की बिक्री और इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद प्रशासन को यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी बात को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीमों द्वारा शहर के सभी प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि इसी जांच अभियान के तहत जब निगम की टीम सेक्टर-57 के क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए पहुंची, तो वहां एक प्रतिष्ठान (दुकान) पर प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल होता हुआ पाया गया। टीम ने सरकारी नियमों के तहत तुरंत कार्रवाई की और संबंधित दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

आंगनवाड़ी वर्कर ने केंद्रीय राज्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

फरीदाबाद,एजेंसी।

भारतीय विरोध दिवस के तहत बुधवार को सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंव हैल्पर ने लंबित मांगों को लेकर फरीदाबाद जिला कमेटी के नेतृत्व में केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा सीटू की प्रधान मालवती व सचिव देवेन्द्री शर्मा,उप प्रधान सुरेन्द्री ,इंद्रा, राजेश व माया आदि ने किया।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। यूनियन की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व जिला सचिव देवेन्द्री शर्मा ने बताया कि पिछले दस महीने से आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सैकड़ों वर्कर्स ने अपनी जेब से किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से वर्कर्स एंड हैल्पर्स के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्राप्त राशन सप्लाई हो रहा है।

जिससे वर्कर्स एंव हैल्पर्स के साथ ही लाभार्थी भी परेशान हैं। आला अधिकारियों को यूनियन द्वारा बार बार पत्र एवं स्मरण पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजग़ी जताई और शीघ्र भुगतान न होने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। प्रदर्शन के दौरान देवेन्द्री शर्मा व मालवती ने कहा कि केंद्रीय आम बजट 2025-26 एवं 2026-27 में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंव हैल्पर्स की लगातार उपेक्षा की गई है।

वर्ष 2018 के बाद से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे वर्कर्स एंड हैल्पर्स के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की बात किए जाने के बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है।

मंत्री राजेश नागर ने सुनीं किसानों व व्यापारियों की समस्याएं

सोहना,एजेंसी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बुधवार को सोहना अनाज मंडी में व्यापारियों व किसानों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही मार्केट कमेटी विभाग द्वारा बनाए गए गेट पास काउंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि साइट न चलने के कारण आज गेहूं की खरीद नहीं हो सकी है। उन्होंने अधिकारियों से सफाई, कैंटीन, पेयजल, बारदाना, लिफ्टिंग आदि के बारे में जानकारी ली। मंडी में अतिक्रमण की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक के पुत्र व समाजसेवी राजकुमार तंवर, मार्किट कमेटी चेयरमैन दयाराम लोहिया, सचिव दिनेश श्योकंद, अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा, व्यापारी विकास गुप्ता, कर्मचारी टेकचंद आदि के अलावा किसान व व्यापारी मौजूद रहे। कस्बे की अनाज मंडी में सरसों की फसल की खरीद 50 फीसदी हुई है, जिसकी खरीद व्यापारी लोग एमएसपी से ज्यादा दामों पर कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक सरसों की खरीद किए जाने के निर्देश नहीं दिए हैं।

राज्य मंत्री ने सरसों की फसल की लिफ्टिंग जल्द कराए जाने के आदेश भी दिए हैं, ताकि गेहूं की खरीद में किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। राजेश नागर ने कहा है कि किसानों की गेहूं की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोहना में नई अनाज मंडी बनाने की घोषणा जल्द ही कि जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि फसली सीजन में किसानों व व्यापारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

स्कूल खुलते ही ट्रांसपोर्ट का झटका, अभिभावकों पर बढ़ा खर्च

गुरुग्राम,एजेंसी।

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल परिवहन व्यवस्था एक बार फिर अभिभावकों की मजबूरी और परेशानी दोनों बन गई है। स्कूल फीस के साथ बढ़ती परिवहन व्यवस्था ने भी अभिभावकों का बजट बिगाड़ दिया है। शहर के अधिकांश स्कूल आवासीय इलाकों से दूर होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र बस सेवा पर निर्भर हैं, वहीं नौकरीपेशा अभिभावक के पास बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ने-लाने का समय नहीं होता। ऐसे में स्कूलों की बस सेवा या निजी तौर पर चलने वाले वैन और कैब ही प्रमुख विकल्प बन जाते हैं।

इसी जरूरत के बीच अब परिवहन फीस में हुई बढ़ोतरी ने अभिभावकों का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे नए सत्र की शुरुआत आर्थिक दबाव के साथ हो रही है। जिले में करीब एक हजार निजी स्कूल हैं, जिनमें से अधिकतर स्कूलों की ओर से परिवहन की सुविधा दी जाती है। ऐसे में ज्यादातर स्कूलों के अभिभावकों के सामने यह दिक्कत सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, इस बार परिवहन फीस में औसतन 10% से 25% तक बढ़ोतरी की गई है। पहले 3-5 किलोमीटर के लिए जहां 1800-2200 रुपये प्रति माह लिए जाते थे।

अब यह बढ़कर 2200-2800 रुपये हो गए हैं। 5-10 किलोमीटर के दायरे में फीस 2500-3200 से बढ़कर 3000-4000 तक पहुंच गई है। दूर रहने वाले छात्रों के लिए यह खर्च 4000 से ऊपर तक जा रहा है। कई स्कूलों ने दूरी के हिसाब से अलग-अलग स्लैब बनाकर फीस तय की है, जिससे हर अभिभावक पर अलग-अलग असर पड़ रहा है। सेक्टर-56 निवासी अभिभावक अमित शर्मा कहते हैं कि पहले ही किताबें और यूनिफॉर्म महंगी हो गई हैं, अब परिवहन फीस भी बढ़ गई है। हर महीने का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है।

सेक्टर-10 की रीना गुप्ता का कहना है कि हमारा घर स्कूल से दूर है, इसलिए बस जरूरी है, लेकिन इस बार बस का किराया इतना बढ़ गया है कि बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि परिवहन की फीस बढ़ाना उनकी मजबूरी है। एक निजी स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार ईंधन के दाम, ड्राइवरों की सैलरी और मेंटेनेंस कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। पिछले एक-दो साल से फीस में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन इस बार लागत के हिसाब से थोड़ा इजाफा करना पड़ा है। कुछ स्कूलों का यह भी कहना है कि वे सुरक्षा मानकों, जीपीएस ट्रैकिंग और बसों के अपग्रेड पर भी खर्च कर रहे हैं, जिससे कुल लागत बढ़ रही है।

छात्रों ने मीडिया की कार्य प्रणाली को समझा

फरीदाबाद,एजेंसी।

रेवाड़ी स्थित केएलपी कॉलेज के मीडिया विद्यार्थियों ने बुधवार को जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग की आधुनिक मीडिया कार्य प्रणाली को करीब से समझा। अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो का अवलोकन करते हुए मल्टी-कैमरा सेटअप, लाइटिंग, टेलीप्रॉम्प्टर और न्यूज बुलेटिन निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों ने ग्रीन रूम, पीसीआर (प्रोडक्शन कंट्रोल रूम), पोस्ट-प्रोडक्शन लैब और रेडियो स्टूडियो का भी दौरा किया। यहां उन्हें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड रिकॉर्डिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन की बारीकियों से अवगत कराया गया। मीडिया विभागाध्यक्ष प्रो. पवन सिंह ने कहा कि ऐसे अंतर-विश्वविद्यालय संवाद छात्रों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सफल पत्रकार बनने के लिए थ्योरी के साथ-साथ स्टूडियो संचालन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग और फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव बेहद जरूरी है। इस अवसर पर जेसी बोस विश्वविद्यालय की फैकल्टी और प्रॉडक्शन टीम ने छात्रों को मीडिया इंडस्ट्री की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही विभाग द्वारा बनाई गई अवार्ड विजेता शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गईं। इस अवसर पर केएलपी कॉलेज के शिक्षक डॉ. अमित मेहता, डॉ. निवेदिता, अंकिता नैनावत और समन्वयक डॉ. रिचा शर्मा मोजूद रही।

RNI.No DLHIN/25/A2841 स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित। संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508 मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com संपादक देवेंद्र सिंह तोमर इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

आईसीएआर ने कृषि को विज्ञान, नवाचार और समाधान से जोड़ाः रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संस्थान इस परिवर्तन का अग्रदूत है, जो ज्ञान को जमीन तक पहुंचाकर किसानों की ताकत को बढ़ा रहा है।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) के 122वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि आईसीएआर ने भारत की कृषि को केवल परंपरा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे विज्ञान, नवाचार और समाधान से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आईसीएआर खेत और प्रयोगशाला के बीच की दूरी को समाप्त करते हुए संस्थान ने हरित क्रांति से लेकर आज की आधुनिक, तकनीक आधारित खेती तक देश को एक नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह संस्थान इस परिवर्तन का अग्रदूत है, जो ज्ञान को जमीन तक पहुंचाकर किसानों की ताकत को बढ़ा रहा है और भारत की कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने आईसीएआर से राजधानी में धूल और प्रदूषण को कम करने और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण के साथ-साथ तरीकें से सहयोग करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से संसाधन बचाने और उनका उपयोग सही तरीके से करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि भूजल, बिजली और पेट्रोल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखा करें। इन संसाधनों को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक काम करें। उन्होंने कहा कि आईसीएआर ने देश में खाद्यान्न संकट को दूर किया। आज देश खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर दूसरे देश की मदद कर रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी रवींद्र इंद्राज सहित संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी और शोधकर्ता उपस्थित रहे।

स्वागत संबोधन में संस्थान के निदेशक, डॉ.सी.एच. श्रीनिवास राव ने गत वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों एवं पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थान ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया, एसडीजी में द्वितीय स्थान, समग्र रूप से 24वां तथा अनुसंधान में 29वां स्थान प्राप्त किया।

इस अवसर पर दिल्ली के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रवीन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि दिल्ली के पारंपरिक जल स्रोत जैसे पहले जिन जोहड़ और तालाबों के रूप में जाने जाते थे और आज 'वॉटर बॉडीज' कहलाते हैं उनका संरक्षण और पुनर्जीवन बेहद जरूरी है। इससे दिल्ली के जल स्तर और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों को सही कीमत मिलनी चाहिए ताकि किसानों को प्रोत्साहन और आर्थिक मजबूती मिल सके।उन्होंने बताया कि शहरीकरण बढ़ने के बावजूद दिल्ली में करीब 50 हजार हेक्टेयर जमीन पर अब भी खेती हो रही है और किसानों का योगदान बेहद अहम है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली,साहस समाचार।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल के दौरान मानवता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स (कोरोना योद्धाओं) के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इन वीर योद्धाओं के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्षों से लंबित आर्थिक सहायता के मामलों का निस्तारण करते हुए प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छह विभिन्न परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक सौंपे। इस सहायता सूची में दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट के एएसआई श्री राधे श्याम का परिवार भी शामिल था, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार 'सम्मान, संवेदना और संकल्प' के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और हर कठिन परिस्थिति में इन परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

सहायता राशि वितरित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भावुक स्वर में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती और यह राशि उस अपूरणीय क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, यह सहायता सरकार के उस अटूट संकल्प का प्रतीक है कि इन कर्मयोगियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली इन नायकों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगी और उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदैव जीवित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने परिवारों को आश्वस्त किया कि भविष्य में भी उन्हें किसी प्रकार की समस्या होने पर सरकार उनके लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उस समय अपनी जान जोखिम में डाली जब पूरी दुनिया संकट में थी, इसलिए उनके परिवारों का ध्यान रखना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कदम की सराहना करते हुए परिजनों ने भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

बच्चों की तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार व एजेंसियों को नोटिस

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बढ़ती बच्चों की तस्करी पर गंभीर चिंता जताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि तमाम निर्देशों और मानक प्रक्रियाओं के बावजूद दिल्ली बच्चों की तस्करी का "मंडी" बन चुकी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से तीखा सवाल किया कि आखिर इस गंभीर समस्या पर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि रेलवे और बस स्टेशनों के आसपास की स्थिति देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां क्या हो रहा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर को निर्देश दिया कि वे मानव तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दें। साथ ही आयोग को दिल्ली में बच्चों की तस्करी से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि प्रभावी उपाय तय किए जा सकें।

याचिका में बताया गया कि वर्ष 2018 से 2024 के बीच रेलवे परिसरों से 84 हजार से अधिक बच्चों को बचाया गया है, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बावजूद तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि कई मामलों में बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बजाय दोबारा तस्करों के हवाले कर दिया गया, जिससे उनकी पुनः तस्करी हुई। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।

अदालत ने निर्देश दिया कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि बाल कल्याण समिति की सेवाओं का प्रभावी उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ताकि बचाए गए बच्चों की दोबारा तस्करी रोकी जा सके। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगे और सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

एमसीडी ने संपत्ति कर संग्रह 46% बढ़कर 3,116 करोड़ पार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर संग्रह का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निगम ने 31 मार्च 2026 तक कुल 3,116.62 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.12 प्रतिशत अधिक है। निगम के असेसमेंट एवं कलेक्शन विभाग के अनुसार यह उपलब्धि बेहतर अनुपालन, सख्त प्रवर्तन और योजनाबद्ध प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता का श्रेय महापौर राजा इकबाल सिंह के नेतृत्व और विभागीय टीम के निरंतर प्रयासों को दिया गया है।

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कुल 13,52,562 करदाताओं से कर संग्रह हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11,33,161 करदाताओं से 2,132.89 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस प्रकार करदाताओं की संख्या में भी लगभग 19.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है संपत्ति कर निपटान योजना 'सुनियो' ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। 31 मार्च 2026 तक 2,06,861 करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया, जिससे 1,236.03 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें 1.47 लाख से अधिक आवासीय संपत्तियों से 242.87 करोड़ रुपये और 59 हजार से अधिक गैर-आवासीय संपत्तियों से 993.52 करोड़ रुपये का संग्रह शामिल है।

इसके अलावा, 1,11,909 नए करदाताओं ने पहली बार संपत्ति कर का भुगतान किया, जिससे 448.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला। यह कर आधार के विस्तार और नागरिकों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। राजस्व बढ़ाने के लिए निगम ने आधुनिक तकनीकों और तृतीय-पक्ष आंकड़ों का सहारा लिया। वाणिज्यिक संपत्तियों की पहचान के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जनरल ट्रेड लाइसेंस और बिजली विभाग के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस प्रक्रिया में 5,808 नई संपत्तियों की पहचान कर 25.68 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया।

वहीं, बिजली वितरण कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर 43,114 नई संपत्तियां चिन्हित की गईं, जिससे लगभग 40.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई। निगम ने लंबे समय से बकाया रखने वाले करदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियों को अटैच भी किया। इसके साथ ही 'सुनियो' योजना की अवधि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें मात्र 5 प्रतिशत पेनल्टी के साथ कर जमा करने का अवसर दिया जा रहा है। निगम अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के कदमों से भविष्य में भी राजस्व संग्रह में वृद्धि जारी रहेगी और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।

दिल्ली में तीन गुने दाम पर सिलिंडर की कालाबाजारी तेज

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राजधानी में एलपीजी गैस सिलिंडर की कमी के बीच अब कालाबाजारी तेजी से बढ़ने लगी है। उपभोक्ताओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग मात्र दो घंटे में सिलिंडर उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले उनसे तीन गुना तक कीमत वसूली जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों पर जहां एक सिलिंडर की कीमत लगभग एक हजार रुपये के आसपास है, वहीं तत्काल डिलीवरी के नाम पर दो से तीन गुना अधिक रकम मांगी जा रही है। इसके बावजूद भी समय पर सिलिंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर गैस आपूर्ति पर पड़ा है, जिससे राजधानी में सिलिंडर की उपलब्धता प्रभावित हुई है। बीते तीन दिनों से कई इलाकों में गैस की कमी के कारण लंबी कतारें देखी जा रही हैं। द्वारका क्षेत्र के निवासी संगठनों का आरोप है कि कुछ बिचौलिये इस संकट का लाभ उठाकर अवैध तरीके से सिलिंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। जरूरतमंद उपभोक्ताओं को तत्काल डिलीवरी का लालच देकर उनसे भारी रकम वसूली जा रही है।

स्थिति यह है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग मजबूरी में अधिक कीमत चुकाने को तैयार हो रहे हैं। कई परिवारों के सामने खाना बनाने तक का संकट खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपूर्ति व्यवस्था जल्द सामान्य नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि कालाबाजारी पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

संवेदनशील इलाकों में अर्द्धसैनिक बल तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राजधानी में हनुमान जयंती पर विभिन्न इलाकों में होने वाले छोटे-बड़े पांच सौ से अधिक धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से संदिग्धों पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिये नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पिकेट्स और भारी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में स्थानीय पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। पुलिस-प्रशासन की तरफ से शोभायात्रा समेत अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए दी गई अनुमति में सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुस्तफाबाद में कांग्रेस का मंथन, कार्यकर्ताओं से पूछा-कौन बने जिला अध्यक्ष

नई दिल्ली,साहस समाचार।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच व्यापक मंथन किया गया। ब्रजपुरी स्थित हनुमान वाटिका में आयोजित इस बैठक में हाईकमान पर्यवेक्षक सुरेन्द्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं का मन टटोला और करावल नगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर राय जानी। बैठक में सुरेन्द्र शर्मा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना ही संगठन को नई दिशा देगा।

कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हारून यूसुफ, पूर्व विधायक हसन अहमद और मुकेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी से ही संगठन मजबूत बनता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को सशक्त बनाने की अपील की।

इस अवसर पर बृजपुरी वार्ड से निगम पार्षद नाजिया जावेद, नेहरू विहार वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी, मुस्तफाबाद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गुलफाम सैफी, हाजी वसीम मलिक, तारा भैया और जावेद चौधरी सहित कई स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

दिल्ली में 45 हजार से ज्यादा राशन कार्ड रद्द

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले करीब 14 महीनों में 45,212 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, वहीं अब फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक लागू करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार यह कार्रवाई 1 जनवरी 2025 से 17 फरवरी 2026 के बीच की गई।

इसका मुख्य उद्देश्य उन अपात्र लोगों को प्रणाली से बाहर करना है, जो नियमों का उल्लंघन कर सब्सिडी वाले अनाज का लाभ ले रहे थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि फिलहाल फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए एआई का उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। आने वाले समय में डेटा विश्लेषण के जरिए संदिग्ध कार्डधारकों की पहचान कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

आंकड़ों के मुताबिक 17 फरवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 15,48,410 राशन कार्ड सक्रिय हैं। इनके माध्यम से लगभग 73 लाख लाभार्थियों को करीब 2,000 उचित दर की दुकानों से हर महीने सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रेणीवार आंकड़ों में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 60,372 और प्राथमिकता वाले परिवारों के 14,88,038 राशन कार्ड शामिल हैं। पिछले दस वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न कारणों से करीब 4.20 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटा के अनुसार दिल्ली में लाभार्थियों की संख्या लगभग पूरी तरह भर चुकी है।विभाग के अनुसार नए राशन कार्ड तभी जारी किए जाते हैं, जब किसी लाभार्थी की मृत्यु, पलायन, कार्ड सरेंडर या अपात्र घोषित होने से स्थान खाली होता है। हालांकि सरकार ने इस वर्ष करीब दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने की योजना बनाई है, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मध्यम श्रेणी में बरकरार हवा, एक्यूआई 113 दर्ज

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली में बीते मंगलवार को हुए बारिश के बावजूद भी हवा मध्यम श्रेणी में बरकरार है। ऐसे में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 113 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। इसमें मंगलवार की तुलना में 58 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में फरीदाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 133 दर्ज किया गया, यह हवा की मध्यम श्रेणी है। वहीं, गाजियाबाद में 130, गुरुग्राम और नोएडा में 94 एक्यूआई दर्ज हुआ।

इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 78 दर्ज किया गया। यह हवा की संतोषजनक श्रेणी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, हवा उत्तर-पूर्व दिशा से 10 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली।

बेटे ने रची पिता से 10 लाख लूट की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

शौक और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता से 10 लाख रुपये लूटने की साजिश रच डाली। लक्ष्मी नगर थाना क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए बेटे सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई पूरी रकम और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। डीसीपी पूर्वी जिला राजीव कुमार ने बताया कि मुखर्जी नगर निवासी पीड़ित यतींद्र कुमार मंगलवार को अपने एक रिश्तेदार को 10 लाख रुपये लौटाने लक्ष्मी नगर इलाके में पहुंचे थे। वह प्रिंटिंग का काम करते हैं। यहां आने के दौरान दौरान स्कूटी सवार दो युवकों ने उनका पीछा किया और मौके पर पहुंचते ही दो राउंड फायरिंग करते हुए उनसे नकदी लूटकर फरार हो गए।

लक्ष्मी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसएचओ इंस्पेक्टर अजीत कुमार झा व एसीपी प्रीत विहार अशोक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी सर्विलांस व मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपितों तक पहुंच बनाई। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वारदात का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का बेटा तवलीन उर्फ रहत (21) है। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो गई।

पुलिस ने उसे मुखर्जी नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में सामने आया कि तवलीन ने अपने दो साथियों मोहित कुमार तिवारी और पंकज के साथ मिलकर पहले से ही पूरी साजिश रची थी। तीनों कुछ समय से साथ रह रहे थे और आसान तरीके से पैसा हासिल कर शौक पूरे करने की योजना बना रहे थे।

डेढ़ हजार से अधिक हथियार-ड्रग तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार। राजधानी को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन कवच-13.0 के तहत 48 घंटे का विशेष अभियान चलाया। इस दौरान हथियार, ड्रग, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 1584 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सभी 15 जिलों में यह अभियान 29 मार्च की शाम से 31 मार्च की शाम तक चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नार्को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 229 एनडीपीएस मामले दर्ज कर 267 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए। इसमें 100 किलोग्राम गांजा, 1.170 किलोग्राम कोकेन, 260.65 ग्राम हेरोइन, 179.11 ग्राम एमडीएसए और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। वहीं, अवैध शराब की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई।

एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस के सवाल, स्पष्टता व सुधार की मांग

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विस्तृत पत्र भेजकर प्रक्रिया में स्पष्टता और आवश्यक सुधार की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि एसआईआर को निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए सवालों के जवाब जरूरी हैं। कांग्रेस की ओर से बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग ने पत्र में प्रक्रिया से जुड़े कई व्यावहारिक और प्रशासनिक मुद्दे उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीएलए को मतदाताओं के फॉर्म सत्यापन की जिम्मेदारी देना न तो व्यावहारिक है और न ही कानूनी रूप से उचित, जबकि यह कार्य केवल निर्वाचन आयोग के अधिकृत अधिकारियों का दायित्व है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि इस व्यवस्था से भविष्य में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों पर सत्यापन का दायित्व डालना आयोग की जिम्मेदारी से बचने जैसा प्रतीत होता है। कांग्रेस ने पत्र में 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाने पर भी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए हैं, ऐसे में पुरानी सूची को वर्तमान क्षेत्रों से बिना स्पष्ट मिलान के उपयोग करना जटिल और भ्रमपूर्ण होगा।

कांग्रेस ने मांग की है कि पुराने और वर्तमान क्षेत्रों का विस्तृत मिलान राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए।

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जाना तय

दुनिया का सबसे ताकतवर देश, अमेरिका इस वक्त अपने देश और वैश्विक स्तर पर दोनों तरफ से भारी दबाव में नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान के साथ लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ देश के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में बड़े पैमाने पर 3300 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का नाम था- नो किंग्स देश में कोई राजा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में राजा जनता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। सवाल उठता है, आखिरकार यह आंदोलन कितना बड़ा है? ट्रंप के खिलाफ विरोध की यह तीसरी बड़ी लहर है। इससे पहले भी लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बार का आंकड़ा सबसे बड़ा है। अमेरिका के सभी राज्यों में इस आंदोलन की आग फैल गई है। 3300 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस आंदोलन की खास बात यह है, यह शहरों के साथ-साथ गांवों में भी देखने को मिला है। लोगों ने खुलकर अपना विरोध जताया है। इस बार सबसे बड़ा विरोध मिनसोटा की राजधानी सेंट पॉल में हुआ। जहां मशहूर सिंगर ब्रूस प्रिंस्टीन ने भी आंदोलन में भाग लिया, और एक खास गाना गाया। जो हाल की एक दुखद घटना से जुड़ा हुआ था। उनके साथ कई बड़े सेलिब्रिटी जिसमें एक्टर्स, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी आंदोलन के मंच पर नजर आए। सवाल उठता है, अमेरिका और आस-पास के देश के लोगों में आखिर किस बात का गुस्सा भरा है?

प्रदर्शन करने वालों के पास कम प्रशासन की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त थी। सबसे ज्यादा नाराजगी ट्रंप सरकार की इमीग्रेशन नीति को लेकर है। लोगों का मानना है, सख्ती और छापेमारी से आम लोग डर और भय के साथ जी रहे हैं। इसके अलावा ईरान के साथ चल रहे संघर्ष का विरोध, ट्रांसजेंडर के अधिकारों में कटौती, अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई जैसे मुद्दों पर लोगों ने खुलकर आवाज उठाई है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और सैंडियागो जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बैनर और नारों के साथ सरकार के खिलाफ यहां पर भारी गुस्सा दिखा। ट्रंप के खिलाफ विरोध के असर की बात की जाए, तो यह विरोध अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। यूरोप के कई देशों में लोग इसी तरह के संदेश के साथ ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। कहीं तानाशाही के खिलाफ तो कहीं युद्ध के खिलाफ नारे लगे। यूरोप के देशों में अच्छीखासी भीड़ सड़कों पर देखने को मिली। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी हाल ही में बैठक से बहिष्कार कर ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। ट्रंप समर्थकों का कहना है, इन प्रदर्शनों को ज्यादा अहमियत नहीं है। उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक एजेंडा है। ट्रंप के विरोध में जो तस्वीर जमीन पर दिख रही है, उसके अनुसार जिस तरह संसद और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों और विशिष्ट वर्ग में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध बढ़ रहा है। उनके ऊपर हाल ही में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। संसद से अनुमति लिए बिना ट्रंप ने यह युद्ध छेड़ा है। जिसके कारण वह संसद में अलग-थलग पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं, जहां ट्रंप को भारी समर्थन मिला था। अमेरिका में माहौल इन दिनों काफी गर्म है। पिछले कुछ महीनो में महंगाई काफी तेजी के साथ बढ़ी है। अमेरिका एक तरफ बाहरी तनाव, दूसरी तरफ आंतरिक विरोध से जूझ रहा है। दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन-प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह देखना अहम होगा। अमेरिका और इजरायल ने जिस तरह से ईरान पर आक्रमण किया है, इसका असर अब सारी दुनिया के देशों पर पड रहा है। ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर मुद्रा और पेट्रोल डॉलर व्यापार को काफी नुकसान हुआ है जिसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पढ़ रहा है। ट्रंप के समय में कर्ज भी तेजी के साथ बढ़ा है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण आम नागरिक बहुत परेशान हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमेज साइको के रूप में देखने को मिल रही है। जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में कहा जा रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाएं। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को मुसीबत में फंसाया है।

बजट से वोटबैंक बढ़ाने की कवायत

मनोज कुमार मिश्र

दिल्ली की समस्या अनोखी है। उसका इलाका तो 1483 किलोमीटर ही रहना है लेकिन आबादी बेहिसाब बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी में हर साल पांच लाख अतिरिक्त आबादी जुड़ती है। देश की राजधानी होने और नोट-वोट की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल इस पर अंकुश लगाना नहीं चाहता है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है।

27 साल लंबे अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता पाने वाली भाजपा ने अपने दूसरे ही बजट में वह सारी घोषणाएं की है, जिससे उसके स्थाई वोट बैंक में बढ़ोतरी हो सके। लगातार तीन बार दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों और साल 2022 से पहले के तीन नगर निगम चुनाव जीतने वाली भाजपा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार छह बार पराजित रही लेकिन पिछले साल केवल ढाई फीसदी के अंतराल से चुनाव जीतकर सत्ता में आई।

इसी 24 मार्च को 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने इसे हरित बजट का नाम दिया। इस बजट में जिस तरह की दनादन घोषणाएं की गई हैं, उससे वास्तव में यह चुनावी बजट जैसा लगता है। अगले साल के आखिर में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली सरकार का एक और बजट ही आ पाएगा। नगर निगम चुनाव 05 दिसंबर, 2022 को हुए थे। साल 2022 से पहले तीन नगर निगम चुनाव जीतने के बावजूद भाजपा का वोटबैंक नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें अपवाद लोकसभा चुनाव ही है। जिसमें भाजपा को दिल्ली में औसत 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं।

इस बजट का फोकस महिला वर्ग है। महिलाओं का समर्थन मिलने से ही बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार राजग और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती रही है। इसी के बूते महाराष्ट्र में फिर से राजग की सरकार बनी। लाडली योजना के बजाए लखपति बिटिया योजना, बिहार की तर्ज पर 9 वीं की 1.30 लाख बच्चियों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। बजट पेश होने के साथ इस पर अमल करते हुए एक समारोह में 1100 बच्चियों को मुख्यमंत्री ने साइकिल बांटी। इस पर सरकार 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 10वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप देने पर दस करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इस पर भी अमल शुरु हो गया है।

महिलाओं की तरह किन्नरों को भी बसों के फ्री पास, एक हजार महिलाओं और 100 किन्नरों को ई-आटो की परमिट, महिला सुरक्षा के तहत डार्क स्पाट खत्म करने और महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के मद में 5110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह अलग विषय है कि सरकार बने साल बीत जाने के बावजूद महिलाओं को पैसे मिलना शुरु नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समिति बनाकर पात्र महिलाओं की पहचान की गई। अब तुरंत नियमित पैसे दिए जाएंगे।

इस बार बजट में 3700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 27 साल बाद पिछले साल फरवरी दिल्ली में बनी भाजपा सरकार ने साल 2025-26 का रिकार्ड एक लाख करोड़ का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के वायदे किए गए थे, उसमें यह बजट भी नाकाफी रहा। दिल्ली में दस साल

प्रचंड बहुमत से सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी (आआपा) पर भाजपा समेत सभी विरोधी दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती रही। अब भाजपा सरकार भी उन मुफ्त की रेवड़ियों को दूसरे साल भी जारी रखने का ऐलान किया। भाजपा को इसका फायदा समझ में आने लगा है। इतना ही नहीं, दनादन मुफ्त बिजली-पानी के अलावा बजट में कई और रेवड़ियों की घोषणा कर दी। इस साल भी होली-दीवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर 260 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह दिल्ली को और हरा-भरा बनाने वाला हरित बजट है। बजट मद का 21 फीसदी धन दिल्ली को हरा-भरा बनाने पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली में ई-आटो, ई-टैक्सी और ई-बसें बड़ी तादाद में चलाई जाएंगी। दिल्ली के अलावा एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में ई-बसों का परिचालन शुरु हो गया है। मेट्रो रेल के चौथे और पांचवें चरण की न केवल मंजूरी दी गई है बल्कि उसके लिए 2224 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इसी तरह नमो भारत के दो नए कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली नगर निगम को इस बार सर्वाधिक 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यार्थी राजनीति के बाद नगर निगम से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। तीन निगमों को एक करके 272 सीटों को 250 सीट करके पांच दिसंबर, 2022 में निगम चुनाव करवाए गए। लगातार तीन बार से निगम की सत्ता में रही भाजपा उस चुनाव में पिछड़ गई और 134 सीटें लाकर आआपा पहली बार नगर निगम की सत्ता में आ गई। उसे हर बार 36 फीसदी के आसपास वोट मिलते रहे। भाजपा को 106 सीटें आई। नगर निगम में दलबदल विरोधी विधेयक लागू नहीं है। दो साल में दल बदलने वाले निगम पार्षदों के बूते भाजपा फिर से निगम में बहुमत में आ गई। सालों बाद केन्द्र के बाद दिल्ली की सत्ता में भाजपा के आने के बाद वह किसी भी तरह से अगले साल होने वाले चुनाव को जीतने का प्रयास करेगी।

वैसे अभी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। उसका सामना करने और उसका निबटारा करने के लिए सरकार को लगातार युद्धस्तर पर काम करना होगा। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के अलावा दिल्ली के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव होता नहीं दिख रहा। इस बजट में नया सचिवालय, कई सरकारी उपक्रमों के भवन और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने इत्यादि की घोषणा की गई है। दस केन्द्रीय विद्यालय और एक सैनिक स्कूल बनाने के वायदे किए गए हैं। पहले के विश्वविद्यालयों के कैंपस बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं।

वायदे के मुताबिक मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आम लोगों को मुफ्त उपचार के लिए आयुष्मान योजना न केवल दिल्ली में लागू किया गया। अबतक इस योजना में सात साख से ज्यादा लोग पंजीकरण कराकर इसका लाभ उठा रहे हैं। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या और वार्ड आदि बढ़ाने की घोषणा तो की गई है लेकिन नए अस्पताल बनाने की घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली में देश का सर्वाधिक न्यूनतम वेतन 22,411 रुपए प्रति महीना लागू किया गया।

कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए पांच सौ पालन केन्द्र खोले गए हैं। परिवहन क्षेत्र में चार हजार से अधिक ई-बसें चलाई गई है। नौ हजार से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नई ईवी नीति, ई- बाइक, ई-टैक्सी को बढ़ावा देने के अलावा दिल्ली के आखिरी छोर तक सार्वजनिक वाहन को पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वैसे सरकार को हाई कोर्ट के हलफनामे के हिसाब से 11 हजार बसों को सड़क पर लाने की भी चुनौती है। यमुना साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।

37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 28 को अपग्रेड किया गया है, नौ पर काम चल कहा है। 12 नए संयंत्र बनेंगे। दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने से लेकर दिल्ली के मूलभूत ढांचे को विकसित करने से लेकर दिल्ली को आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त शहर बनाने के प्रयास के लिए दिल्ली सरकार केन्द्र की सरकार के सहयोग से दिन-रात काम कर रही है।

1993 में दिल्ली में नए प्रशासनिक ढांचे में विधानसभा बनने पर हुए पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनी। पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद उस सरकार ने कई ठोस काम किए। पहली बार यमुना के जल में राज्य की तरह दिल्ली को हिस्सा मिला। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकार बढ़ाकर बिजली बोर्ड बनाकर बिजली का उत्पादन बढ़ाया। नए स्कूल-कॉलेज ही नहीं, नया विश्वविद्यालय बनाया गया। नए अस्पताल बने और बड़ी संख्या में दिल्ली के हर कोने में निर्माण कार्य हुए। दिल्ली मेट्रो की नींव रखी गई। 1984 के सिख दंगा पीडितों को न्याय दिलाने के प्रयास हुए।

इस सिलसिले को साल 1998 में शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने और आगे बढ़ाया। दिल्ली के मूलभूत ढांचे के विकसित करने की सर्वाधिक श्रेय शीला दीक्षित के जाता है। पूरी दिल्ली में काम हुए। दिल्ली फ्लाईओवर का शहर हो गया।

फिर दस साल प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी(आआपा) की सरकार बनी। उसके बाद सालभर पहले भाजपा की सरकार बनी। चुनाव प्रचार में भाजपा के नेताओं के वायदों में से कुछ पर तो अमल शुरू हो गए हैं लेकिन काफी काम अभी करने बाकी हैं। आआपा शासन के दस साल ने दिल्ली में विकास की दिशा ही बदल दी थी, जिसे वापस पटरी पर लाना भाजपा सरकार के लिए पहली चुनौती थी।

दिल्ली की समस्या अनोखी है। उसका इलाका तो 1483 किलोमीटर ही रहना है लेकिन आबादी बेहिसाब बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी में हर साल पांच लाख अतिरिक्त आबादी जुड़ती है। देश की राजधानी होने और नोट-वोट की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल इस पर अंकुश लगाना नहीं चाहता है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। मौसम से लेकर बिजली-पानी के लिए दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली की सड़क भी एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। लोक निर्माण विभाग की 1400 किलोमीटर सड़कों में से पहले साल में 750 किलोमीटर सड़कों की वाल-टू-वाल कारपेंटिंग किया जाएगा। सड़कों पर आवागमन सुगम करने के लिए नए फ्लाईओवर और 40 नए फुट ओवरब्रिज का काम हो रहा है।

दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वायु प्रदूषण शमन योजना बनाई गई है। सरकार का फोकस दिल्ली की साफ सफाई पर है, इसमें उसे काफी सफलता मिली। ओलंपिक आदि जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को बीस लाख रुपए की सहायता दी जा रही है।

आरसीबी क्यों बना आईपीएल का इतना बड़ा ब्रांड?

विवेक शुक्ला

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस साल शुरू होने से पहले ही बड़ा धमाका हो गया। यह धमाका तब हुआ जब खबर आई कि बैंगलुरु की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इतिहास रच दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (डीएजियो की सहायक कंपनी) ने आरसीबी को आदित्य बिड़ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स (डेविड ब्लिट्जर) और ब्लैकस्टोन के BXPE फंड के कंसोर्टियम को 1.78 बिलियन डॉलर (लगभग 16,660 करोड़ रुपये) में बेच दिया। यह आईपीएल फ्रेंचाइजी इतिहास की अब तक की सबसे महंगी डील बन गई है। इस डील ने राजस्थान रॉयल्स की 15,290 करोड़ रुपये की बिक्री को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरसीबी इतनी महंगी क्यों बिकी? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे वैश्विक स्तर पर इतना आकर्षक एसेट बनाता है?

आरसीबी की कहानी 2008 में आईपीएल के पहले सीजन से शुरू होती है। विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज ने इसे 111.6 मिलियन डॉलर (तब करीब 446 करोड़ रुपये) में खरीदा था। उस समय यह मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी सबसे महंगी टीम थी।

बाद में डीएजियो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के जरिए टीम पर नियंत्रण हासिल किया। 18 वर्षों में आरसीबी की वैल्यूएशन में लगभग 1495% का उछाल आया, यानी इसकी कीमत मूल निवेश से लगभग 16 गुना बढ़ गई। यह सिर्फ खेल प्रदर्शन का परिणाम नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड बिल्डिंग का उदाहरण है।

2025 की जीतः टर्निंग पॉइंट बीते साल 2025 में आरसीबी ने आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग (WPL) दोनों खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने टीम को डिफेंडिंग चैंपियन बना दिया और उसके ब्रांड

को नई ऊंचाई दी। हालांकि, सिर्फ ट्रॉफियां ही इसकी ऊंची वैल्यू की वजह नहीं हैं। असली ताकत इसके ब्रांड वैल्यू, फैन बेस और मार्केट पोजिशन में छिपी है।

ब्रांड पावर और विशाल फैन बेस आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल और वफादार फैन बेस है। "आरसीबी आर्मी" न सिर्फ बैंगलुरु बल्कि पूरे दक्षिण भारत और देशभर में फैली हुई है। यह टीम भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन चुकी है।

ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, आरसीबी का ब्रांड वैल्यू 269 मिलियन डॉलर (लगभग 2,486 करोड़ रुपये) है, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा है। यह मुंबई इंडियंस (242 मिलियन) और चेन्नई सुपर किंग्स (235 मिलियन) से भी आगे है।

सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, यूट्यूब व्यूज और डिजिटल एंगेजमेंट के मामले में भी आरसीबी शीर्ष पर बनी हुई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम का शानदार माहौल और लगातार भरी रहने वाली दर्शक दीर्घाएं गेट रेवेन्यू को मजबूत बनाती हैं।

मजबूत रेवेन्यू मॉडल बैंगलुरु एक प्रमुख टेक हब होने के कारण आरसीबी को कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स भी आसानी से मिलती हैं। 2025 में टीम की कुल रेवेन्यू 504 करोड़ रुपये रही।

इसमें बीसीसीआई के सेंट्रल रेवेन्यू पूल (ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप शेयर) का बड़ा योगदान रहा, लेकिन टीम-ओन्ड रेवेन्यू जैसे मर्चेंडाइजिंग, टिकट बिक्री और लोकल स्पॉन्सर्स से भी 270-300 करोड़ रुपये की कमाई हुई। यह विविध रेवेन्यू मॉडल निवेशकों के लिए इसे और आकर्षक बनाता है। विराट कोहलीः सबसे बड़ा ब्रांड एसेट आरसीबी की पहचान उसके स्टार खिलाड़ी विराट कोहली से जुड़ी है। 2008 से लगातार एक ही टीम के लिए खेलने वाले कोहली आईपीएल के सबसे वफादार खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता, ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल अपील ने आरसीबी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोहली अकेले टीम की वैल्यू में 200-300 मिलियन डॉलर (लगभग 1,700-2,500 करोड़ रुपये) तक का योगदान देते हैं।

आईपीएल 2016 में 973 रन बनाने वाले कोहली आज भी 37 साल की उम्र में फिटनेस और प्रदर्शन का शानदार उदाहरण हैं। उनकी मौजूदगी ने आरसीबी को "ट्रॉफीलेस" दौर में भी चर्चा में बनाए रखा।

आईपीएलः एक ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म आईपीएल का कुल बिजनेस वैल्यू 2025 में 18.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2023-27 के मीडिया राइट्स डील ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

सेंट्रल रेवेन्यू शेयर हर टीम को स्थिर आय देता है, जबकि डिजिटल कंटेंट, मर्चेंडाइज और इंटरनेशनल एक्सपैंशन से अतिरिक्त कमाई के रास्ते खुलते हैं। यही वजह है कि ब्लैकस्टोन और बोल्ट वेंचर्स जैसे वैश्विक निवेशक इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नए मालिकों की रणनीतिक ताकत आरसीबी के नए मालिकों का कंसोर्टियम भी इस डील को खास बनाता है। आदित्य बिड़ला ग्रुप इंडस्ट्रियल ताकत और ब्रांडिंग विशेषज्ञता लाएगा। टाइम्स ग्रुप अपनी मीडिया संपत्तियों के जरिए टीम की डिजिटल और वैश्विक पहुंच को बढ़ाएगा।

ब्लैकस्टोन की वित्तीय क्षमता और डेविड ब्लिट्जर का स्पोर्ट्स निवेश अनुभव मिलकर आरसीबी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। खास बात यह है कि टीम का नाम "रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु" ही रहेगा। अंडरडॉग से चैंपियन तक आरसीबी की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि संघर्ष और भावनात्मक जुड़ाव की कहानी है। 17 साल तक ट्रॉफी का इंतजार और फिर 2025 में डबल चैंपियन बनना- यह सफर इसे खास बनाता है। बैंगलुरु का युवा और टेक-सेवी ऑडियंस, कोहली का इमोशनल कनेक्शन और मजबूत फैन एंगेजमेंट इसे एक "इमोशनल ब्रांड" बनाते हैं। नए मालिकों के पास आरसीबी को और आगे ले जाने के कई मौके हैं। क्रिकेट अकादमी, महिला क्रिकेट, डिजिटल कंटेंट और ग्लोबल टूर जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है।

यह डील इस बात का प्रतीक है कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, बल्कि एक "स्पोर्ट्स-मीडिया-एंटरटेनमेंट बिजनेस" बन चुका है।

आरसीबी की यह ऐतिहासिक बिक्री साबित करती है कि आज के दौर में ब्रांड पावर, फैन लॉयल्टी और मार्केट वैल्यू ट्रॉफियों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। बैंगलुरु की सड़कों पर गूंजने वाला "आरसीबी" का नारा अब और बुलंद होगा। आरसीबी अब सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं, बल्कि 16,660 करोड़ रुपये का एक ग्लोबल ब्रांड है- जिसकी असली ताकत उसके फैंस के दिलों में बसती है।

श्री हनुमानः रामभक्ति के विग्रहवान स्वरूप

हनुमान जी महाराज, परात्पर ब्रह्म, सच्चिदानन्द स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के निष्ठावान सेवक, निष्काम भक्त और उनके अन्तरङ्ग पार्षद हैं। रामभक्ति के विग्रहवान स्वरूप श्री हनुमानजी भक्ति की उच्चतम पराकाष्ठा पर आसीन है और उनके जीवन में प्रेमा भक्ति, तात्विक ज्ञान और निष्काम कर्म योग का समुच्चय विद्यमान है।

श्री हनुमानजी राम मिलन के प्रमुख सेतु हैं और अपने आराधकों को जीवन के चरम लक्ष्य रामभक्ति की और अग्रसर करते हैं, वे रामभक्तों के परम आश्रय और संकटापन्न स्थिति में उनके संकटों का निवारण करते हुए उनके जीवन में शुभ मङ्गल का संचार करने वाले प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं। भगवान श्रीराम की वनगमन लीला में एक प्रमुख पात्र के रूप में उनकी भूमिका अपने स्वामी श्रीराम के निष्ठावान सेवक के रूप में ही नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर पुत्र के समान आज्ञाकारी, बंधु के समान हितकारी, द्विविधा की स्थिति में गुरु के समान पथ प्रदर्शक तथा विषम परिस्थितियों में मित्र के समान सहयोगी के रूप में भी उल्लेख किए जाने योग्य है। वस्तुतः हनुमानजी जैसा निष्ठावान, समर्पित एवं निष्काम भक्त न तो सृष्टि में पहले कभी हुआ और न आगे कभी हो सकता है। उनके बगैर श्रीरामचरित का पूरी तरह बखान नहीं किया जा सकता। विराट वैभव से परिपूर्ण श्री हनुमानजी विनयशील हैं और रामकाज में अत्यंत लघु रुप धारण कर लेते हैं। हनुमानजी भगवान श्रीराम की आज्ञा पाकर जब सीता माता की खोज हेतु निकले तो वे अत्यंत लघु रूप में आकाश मार्ग से गमन करते हुए लंका पहुंचे। श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका की भूमि पर कदम रखने के पहले जहां उन्होंने अपने स्वामी श्रीराम का स्मरण करते हुए लंका की सीमा में प्रवेश किया, वहीं जब लंका नगरी में माता सीता की खोज शुरू की, तब भी लघु रूप धारण कर सर्वप्रथम अपने स्वामी श्रीराम का स्मरण करते हुए सीताजी का अनुसंधान करने लगे। हनुमानजी शुद्ध भक्त हैं इसलिए अहंकार रहित हैं और उनके द्वारा रामकाज निष्पादन हमें प्रेरित करता है कि किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटा हो जाना ही ठीक है। अहंकार महान उद्देश्यों की पूर्ति में सदैव बाधक होता है, परिणामस्वरूप अहंकार से कोई महान कार्य अपने मुकाम पर पहुंचने में पूरी तरह सफल नहीं होता इसलिए हनुमानजी अपने स्वामी श्रीराम की आज्ञा पाकर जब सीता माता की खोज हेतु निकले तो अपने मुख में राम नाम की विराट सत्ता को स्थापित कर लिया किंतु अपने स्वरूप को अत्यंत लघु आकार देते हुए लंकापुरी में सीता माता की खोज करने लगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव द्वारा अपने स्वामी श्रीराम की सेवा की तीव्र अभिप्सा के निमित्त उन्होंने ग्यारहवें रुद्र के रूप में वायुदेव केसरी और देवी अञ्जना के पुत्र हनुमान के रूप में जन्म लिया और भगवान श्रीराम की सेवा की अपनी अभिलाषा पूरी की। पुराणों के अनुसार चूंकि भगवान विष्णु ने रामावतार में पुरुष रुप धारण किया था और भगवान शिव उनकी सेवा के अभिलाषी थे, ऐसे में यदि मनुष्य रूप में जन्म लेकर सेवा करते तो यह दास भाव के अनुकूल नहीं होता इसलिए उन्होंने मनुष्य से निम्नतर वानर योनि में जन्म लेकर दास भाव से अपने स्वामी भगवान श्रीराम की सेवा की। श्रीरामचरितमानस के अनुसार हनुमानजी ने गतिमान सूर्यदेव से तादात्म्य स्थापित करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण की, अपने दिव्य गुणों से वे सूर्यदेव के भी स्नेह भाजन हुए और उनसे प्रखर बुद्धि, दिव्य ज्ञान सहित तेज, ओज, बुद्धि और बल पा गए। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि एवं हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जब श्री हनुमान विद्या अध्ययन हेतु भगवान सूर्य के पास गए तो सूर्यदेव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सदैव गतिमान हूं और तुम्हारे लिए मेरे सामने बैठना संभव नहीं इसलिए मैं तुम्हे कैसे शिक्षा दूंगा? तभी हनुमानजी ने सूर्याभिमुख होकर आकाश मार्ग में गमन करना शुरू कर दिया और उनके समक्ष उनसे संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। उधर स्वर्ग स्थित देवताओं ने जब यह अद्भुत एवं विस्मयकारी दृश्य देखा तो सब के सब हतप्रभ रह गए और हनुमानजी के धैर्य, शौर्य, साहस और वीरता की प्रशंसा करने लगे। हमारे वेद, उपनिषद् एवं पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्रीराम के पावन नाम की बड़ी महिमा का बखान किया गया है और हनुमानजी महाराज तो भगवान श्रीराम के अतिप्रिय दास हैं, रुद्रावतार हैं।

रेलवे ने 2025-26 में यात्री और माल ढुलाई दोनों में बनाया रिकॉर्ड : वैष्णव

नई दिल्ली, एजेंसी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेल ने 2025-26 में 741 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराकर और 1670 मिलियन टन माल ढुलाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो रेल नेटवर्क की बढ़ती क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था में उसकी अहम भूमिका को दर्शाता है।

वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 2025-26 में भारतीय रेल ने 741 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराई, जो 2024-25 के 716 करोड़ यात्रियों की तुलना में 3.54 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही यात्री राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में जहां यह 75,500 करोड़ रुपये था, वहीं 2025-26 में बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ रुपये हो गया, जो 5.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे को मिले रिकॉर्ड बजट आवंटन और पिछले एक दशक में किए गए भारी निवेश का सीधा लाभ अब दिख रहा है। रेलवे गरीबों और मध्यम वर्ग की सवारी है और पिछले 10 वर्षों में हुए निवेश का फायदा समाज के हर वर्ग को मिला है।

माल ढुलाई के क्षेत्र में भी रेलवे ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वैष्णव ने बताया कि 2025-26 में भारतीय रेल ने 1670 मिलियन टन (एमटी) माल का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.25 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही वैगनों की संख्या में 4.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,79,12,271 से बढ़कर 2,91,86,475 हो गई।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि दर्शाती है कि रेलवे देश में किफायती, विश्वसनीय और कुशल लॉजिस्टिक्स माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है।

माल ढुलाई में वृद्धि के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि उर्वरक तथा 'पिग आयरन और तैयार स्टील' क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उर्वरक परिवहन में 13.49 प्रतिशत और पिग आयरन एवं स्टील में 13.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों ने भी इस वृद्धि को मजबूती दी। लौह अयस्क का परिवहन 6.74 प्रतिशत बढ़कर 190.12 मिलियन टन हो गया, जबकि सीमेंट ढुलाई में 4.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 157.17 मिलियन टन तक पहुंच गया। इससे देश में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार का संकेत मिलता है।

राजस्व के मोर्चे पर भी रेलवे ने अच्छा प्रदर्शन किया है। माल ढुलाई से आय 2025-26 में बढ़कर लगभग 1,77,754 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष के 1,75,302 करोड़ रुपये की तुलना में 1.44 प्रतिशत अधिक है। आय के प्रमुख स्रोतों में लौह अयस्क, सीमेंट, पिग आयरन एवं स्टील, उर्वरक, खाद्यान्न और खनिज तेल शामिल रहे। क्षेत्रवार प्रदर्शन में भी संतुलित वृद्धि दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 14.89 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे (12.62 प्रतिशत), पूर्वी तट रेलवे (10.42 प्रतिशत) और पश्चिम मध्य रेलवे (10.06 प्रतिशत) ने भी दो अंकों की वृद्धि दर्ज की।

अन्य जोनों में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, जिनमें पूर्वी रेलवे (0.78 प्रतिशत), पूर्व मध्य रेलवे (0.39 प्रतिशत), उत्तर पूर्वी रेलवे (0.25 प्रतिशत), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (6.75 प्रतिशत), उत्तर पश्चिम रेलवे (5.17 प्रतिशत), दक्षिण मध्य रेलवे (2.59 प्रतिशत), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (3.18 प्रतिशत), दक्षिण रेलवे (1.10 प्रतिशत) और पश्चिम रेलवे (3.57 प्रतिशत) शामिल हैं।

वैष्णव ने कहा कि यह व्यापक वृद्धि देशभर में रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में सुधार और क्षेत्रीय संतुलित विकास को दर्शाती है। संचालन के स्तर पर भी रेलवे ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि बीते वित्त वर्ष में 76,352 विशेष ट्रेनें चलाई गईं, जबकि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 25,000 ट्रेनें नेटवर्क पर संचालित हो रही हैं।

बंगाल की स्थिति चिंताजनक : मिलिंद परांडे

कोलकाता, एजेंसी। विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन सचिव मिलिंद परांडे ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंदू मतदाताओं से बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

एक संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के अपने दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि देश के कई हिस्सों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है, लेकिन बंगाल की स्थिति चिंताजनक दिखाई देती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

परांडे ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जमीन की मांग की गई है और इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जरूरत है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं तथा इसके लिए उन्होंने संबंधित संस्थाओं का आभार भी जताया।

लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने दक्षिणी कमान का कार्यभार किया ग्रहण

जयपुर, एजेंसी।

लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने बुधवार एक अप्रैल को जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का स्थान लिया है, जिन्होंने आज उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है।

डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने जानकारी दी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व कैडेट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने जून 1988 में महार रेजिमेंट में कमीशन लिया। लगभग चार दशकों के विशिष्ट सैन्य करियर में उन्होंने विविध संचालनात्मक परिदृश्यों में व्यापक कमांड एवं स्टाफ नियुक्तियों का दायित्व संभाला है।

जनरल अधिकारी ने अर्द्ध-विकसित क्षेत्र तथा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक इन्फैंट्री बटालियन को कमान किया है, साथ ही स्ट्राइक कोर में इन्फैंट्री ब्रिगेड, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स तथा उत्तरी कमान में पिवट कोर की कमान भी की है।

उनके संचालनात्मक अनुभव में ऑपरेशन पवन में भागीदारी, इथियोपिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा तथा नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों एवं काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों में अनेक कार्यकाल शामिल हैं। वह कर्नल ऑफ़ महार रेजिमेंट भी हैं।

उपराष्ट्रपति ने टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन किया

नई दिल्ली, एजेंसी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को यहां संविधान सदन में राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक 'टाइड्स ऑफ टाइमः संसद में भित्तिचित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास' का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने संसद में बने भित्ति चित्रों को भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बताया और भारत को "लोकतंत्र की जननी" कहा।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान सदन में स्थापित भित्ति चित्र केवल कला कृतियां नहीं हैं, बल्कि वे भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत यात्रा को दर्शाने वाली दृश्य कथाएं हैं।

कांग्रेस ने एसआईआर विरोधी आंदोलन का साथ नहीं दिया : ममता

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के समर्थन में भी आगे नहीं आई।

मुर्शिदाबाद जिले के नबग्राम में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने कई बार उनसे विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ संयुक्त रूप से आंदोलन करने तथा भारत निर्वाचन आयोग के पास साथ जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने हमारी अपील स्वीकार नहीं की। जब पुनरीक्षण का काम चल रहा था तब उन्होंने जनता की चिंता नहीं की। उस समय केवल तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही मतदाताओं के साथ खड़े थे।

उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग पर दक्षिण कोलकाता स्थित उनके विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर को विशेष रूप से निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, भवानीपुर में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगी और अंततः जीतूंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक, जनजातीय तथा पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाया गया।

पंजाब की भाईचारे की एकता को तोड़ नहीं सकतीं अलगाववादी ताकतें : जाखड़

चंडीगढ़, एजेंसी।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कटघरे में आ गई है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक अश्वनी शर्मा दो दिन से इसी कार्यालय में रूके हुए थे और धमाके से कुछ समय पहले ही वह दिल्ली के लिए रवाना हुए।

बम धमाके के बाद पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पहले से पंजाब के थानों पर लगातार ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। फिर बीते दिन होशियारपुर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया और आज चंडीगढ़ में भाजपा के राज्य स्तरीय कार्यालय पर हमला हुआ है। यह घटनाओं की श्रृंखला राज्य की साम्प्रदायिक एकता को तोडने की कोशिशों का संकेत है। दूसरी ओर सीमावर्ती राज्य की सरकार इन सबको रोकने में असफल साबित हो रही है, जिसके कारण अब पंजाब की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का असर चंडीगढ़ तक पहुंचने लगा है।

अलगाववादी ताकतें चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे पंजाब की भाईचारे की एकता को तोड़ नहीं सकतीं।

भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में भाजपा पंजाब कार्यालय के बाहर बम ब्लास्ट की घटना चौंकाने वाली और बेहद चिंताजनक है। गंभीर बात यह है कि पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पिछले दो दिनों से उसी कार्यालय में मौजूद थे और कुछ समय पहले ही दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं।

ओडिशा में विधायकों के वेतन वृद्धि से जुड़े चार विधेयक वापस

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा में विधायकों, मंत्रियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन वृद्धि से संबंधित चारों विधेयकों को अंततः राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इन विधेयकों की वापसी का निर्णय विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने मंगलवार को विधानसभा में इन चारों विधेयकों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे वॉयस वोट से मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि यद्यपि विधेयक पहले सर्वसम्मति से पारित हुए थे, लेकिन बाद में कई सदस्यों ने इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता जताई।

सरकार ने सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए विधेयकों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

सीमा गांव देश की पहली रक्षा पंक्ति, विकास में प्राथमिकता जरूरी: मनोज सिन्हा

जम्मू, एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को सीमा से सटे गांवों को ₹भारत की पहली रक्षा पंक्ति₹ बताते हुए कहा कि इन गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में माखवाल गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र के निवासी साहस, त्याग और धैर्य के प्रतीक हैं और उनकी सेवा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार के रूप में दिखनी चाहिए।

उन्होंने कहा, सीमा के गांव देश के अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव हैं। यहां रहने वाले लोग हर पल देश की रक्षा में खड़े रहते हैं। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी परिवार की जरूरत अनदेखी न हो और जहां योजनाएं कम पड़ें, वहां तुरंत समाधान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि माखवाल और अन्य सीमा गांवों का विकास उनके लिए भावना, संकल्प और जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के वादों और जमीनी स्तर पर मिलने वाले लाभों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सीमा गांवों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीमा क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू जिले के सभी 541 सीमा गांवों को समान ऊर्जा और दृष्टि के साथ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हर सीमा गांव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और मासिक प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए।

उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर सीमा गांव में बेहतर सड़कें, पूर्ण रूप से कार्यरत स्कूल और युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि माखवाल का हर बच्चा देश के किसी बड़े शहर के बच्चे की तरह शिक्षा प्राप्त करे और हर किसान को बेहतर बीज, सिंचाई और बाजार की सुविधा मिले। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सीमा गांवों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही दिशा देने की है।

उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की भी बात कही।

सार समाचार

प्रधानमंत्री मोदी नौ अप्रैल को नारायणगढ़ में करेंगे चुनावी जनसभा

पश्चिम मेदिनीपुर, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी नौ अप्रैल को नारायणगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इस सभा में वह नारायणगढ़ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाप्रसाद गिरी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बुधवार शाम को रमा प्रसाद गिरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभा को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी ओर इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा रानी माइती के समर्थन में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां जनसभा कर चुकी हैं। ऐसे में नारायणगढ़ अब सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले लिएंडर पेस

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा नेता और पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच खेल, युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा, "लिएंडर पेस के साथ शानदार मुलाकात हुई। भारत को टेनिस में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। खेल और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच सराहनीय है।" मोदी ने पेस के खेल जगत में योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है।

राउत पहले शिवाजी के वंशजों से माफी मांगें, फिर इतिहास पर बोलें: बन

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने बुधवार को कहा कि सरसेनापति हंबीरराव मोहिते की पुत्री तारा रानी के बारे में एक जैन मुनि के बयान का कोई समर्थन नहीं करता है हालांकि शिवसेना(यूबीटी) नेता संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशावली के प्रमाण मांगे थे जिसके लिए उन्हें शिवाजी के वंशजों से माफी मांगनी चाहिए।

बन ने कहा कि शिवाजी महाराज के वंशजों के प्रमाण मांगने के लिए श्री राउत को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद ही मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास पर बोलना चाहिए। इस मामले को लेकर उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब जैन मुनि आचार्य नयन पद्मसागर ने दावा किया कि मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते की पुत्री और छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू महारानी तारा रानी एक जैन रानी थीं।

मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जैन मुनि ने दावा किया कि तारा रानी जैन समुदाय से थीं और उनका जन्म एक जैन योद्धा के रूप में औरंगजेब को नष्ट करने के लिए हुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मराठी भाषा का निर्माण एक जैन आचार्य ने किया था। राउत ने इन टिप्पणियों पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुनि के अधिकार पर सवाल उठाया कि वह अपनी मर्जी से तारा रानी को जैन कैसे घोषित कर सकते हैं।

बन ने कहा कि श्री राउत ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसलिए उन्हें अनावश्यक रूप से हिंदुत्व, महाराष्ट्र धर्म या मराठा धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, जिन्होंने सत्ता के लिए औरंगजेब का धर्म स्वीकार कर लिया, उन्हें धर्म या धार्मिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे यह अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कमजोर नहीं है, बल्कि श्री राउत कमजोर हैं।

उन्होंने कहा कि देवभाऊ (देवेन्द्र फडणवीस) के नेतृत्व में राज्य प्रगति कर रहा है, और इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता श्री राउत को निर्वाचित नहीं कर सकती और महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा, नगर पालिका और जिला परिषद चुनावों में उद्धव ठाकरे गुट को उसकी जगह दिखा दी है।

कोलकाता में ईडी का छापा

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बुधवार सुबह कोलकाता के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। इनमें दक्षिण कोलकाता के कसबा इलाके के कारोबारी विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू का आवास भी शामिल है। इसके अलावा बालीगंज स्थित एक कंपनी के कार्यालय सहित कई जगहों पर भी तलाशी ली गई। ईडी सूत्रों के अनुसार सोना पप्पू के खिलाफ पहले से ही कई प्राथमिकी दर्ज हैं। उन पर वसूली, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप हैं। इनमें से चार-पांच मामलों पर पिछले कुछ दिनों से जांच चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को यह कार्रवाई की गई।

सरकार ने कृषि क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला को बताया स्थिर

नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि ईंधन के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला भी स्थिर बनी हुई है। सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आगामी खरीफ सीजन के लिए आवश्यक इनपुट सामग्री की व्यापक समीक्षा की है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने बुधवार को यहां अयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में प्रमुख कृषि संकेतकों पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि थोक मूल्य नियंत्रण में है, जबकि सभी कृषि जिंसों की थोक कीमतों की लगातार निगरानी की जा रही है। ये कीमतें पिछले कुछ वर्षों की तरह ही सामान्य दायरे में हैं। मनिंदर कौर द्विवेदी ने कहा कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें भी निर्धारित दायरे में हैं और सब्जियों के दाम और थोक स्तर पर इनमें सुधार की प्रवृत्ति दिख रही है। उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ समन्वय के माध्यम से यह पुष्टि की गई है कि खरीफ सीजन के लिए बीजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इस सीजन के लिए कुल 166.46 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता का अनुमान है।

महाराष्ट्र में आरटीई कोटे की सीटों के लिए रिकॉर्ड आवेदन

मुंबई,एजेंसी।

महाराष्ट्र में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए 2.87 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संख्या उपलब्ध 1,14,833 सीटों से कहीं अधिक है, जो राज्य के 8,701 स्कूलों में मौजूद हैं। इससे अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

ऑनलाइन लॉटरी और आगे की प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए संचालित की जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर (आमतौर पर कक्षा 1) पर 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इन छात्रों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। पात्रता के लिए महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है और आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा (जहां लागू हो) जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ एडवोकेट डा. आदिश अग्रवाला इसके अध्यक्ष है

मुन्ने भारती ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र बनाये गये

नई दिल्ली,साहस समाचार।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ एडवोकेट डा. आदिश अग्रवाला ने ओखला प्रेस क्लब (रजि) चेयरमैन, प्रसिद्ध समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार एवं एडवोकेट (डा) एम अतहर उद्दीन मुन्ने भारती को ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का मीडिया एडवाइज़र सर्वसम्मति से बनाया गया है। डा.आदिश अग्रवाला ने उनके मनोयन पर कहा कि मुन्ने भारती लगभग 30 सालों से इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे है । मुन्ने भारती देश के पहले पत्रकार है जिन्होंने पत्रकारिता कार्य के साथ सोशल वर्क करते हुए बिहार राज्य के वैशाली ज़िले के गांव में 5-6 राज्य सभा सांसदों के सांसद निधि के सहयोग गाँव में करोड़ों रुपया का काम सरकारी तंत्र के सहयोग से काम कराया। जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण। करनेजी उर्दू विद्यालय भवन निर्माण, कब्रिस्तान चारदीवारी, सड़क इत्यादि कार्य करा कर कीर्तिमान स्थापित किया। जबकि स्थानीय प्रशासन का सहयोग ना मिल पाने की वजह से करोड़ों की सांसद निधि वापस चली गई।

इसके अलावा मुन्ने भारती ने अपने पैतृक गांव में सैकड़ो विधवाओं को ग़ैर सरकारी लोगों के सहयोग से पेंशन दिलाई । करीना काल में दूसरों की मदद के लिए सड़क पर रहे यही वजह थी की वो भी करोना की चपेट में आ गए और मौत और ज़िंदगी के बीच नई दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में जूझते रहे । इनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जवान भी लगे रहे । करोना काल में दिल्ली के ओखला इलाक़े में जहाँ ज़रूरत मंद लोगों तक रातों में जाग कर उनके घरों को चिन्हित कर उनके घर खाना पहुचाते थे वही जब लोग अस्पताल में एडमिट होने के लिए परेशान थे उस समय सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया।

मुन्ने भारती ने पत्रकारिता क्षेत्र में रहते हुए मानवता और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अहम काम किए है । सैकड़ों ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों की कई लाख रुपया की फीस जमा कराकर शिक्षा की तरफ़ अग्रसारित किया है।

स्थानीय लोगों का कहना है जब बिहार में बाढ़ आई थी उसके चपेट में करनेजी गांव भी था । लोग सड़क पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर थे और प्रशासन का दूर दूर तक पता नहीं था उस समय मुन्ने भारती अपनी ग़ैर सरकारी संस्था करनेजी फाउंडेशन और प्रसिद्ध एनजीओ गूँज के सहयोग से लगभग 10 लाख रुपया का ज़रूरत का सामान गाँव भेजा, जिसको कार्यकर्ताओं ने लोगों तक पहुँचाया। उन्हें सम्मान देने में कृषि,यूथ, स्पोर्ट्स, सामाजिक कार्य सहित कई अन्य क्षेत्र में लोगों की प्रतिभा को देखते हुए सम्मानित किया गया। मुन्ने भारती को चीफ जस्टिस और इंडिया द्वारा नेशनल लॉ डे अवार्ड सुप्रीम कोर्ट में सम्मानित किया जा चुका है । इसके अलावा रेडियो मॉस्को एफ़ सी अवार्ड, सहित अनेको अहम सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

झारखंड सरकार और जेएसएससी की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जेलों में रिक्त पड़े पदों को भरने में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई है

रांची, एजेंसी।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में मैनपावर की भारी कमी पर राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जेलों में रिक्त पड़े पदों को भरने में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य के गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को 1 मई तक व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार और जेएसएससी की ओर से रिक्तियों को भरने के संबंध में वास्तविक जानकारी छिपाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि केवल समय लेने और आश्वासन देने के नाम पर जेलों में नियुक्ति प्रक्रिया को टालना पूरी तरह अनुचित है। अदालत ने साफ हिदायत दी कि स्टेटस रिपोर्ट गृह सचिव और जेएसएससी सचिव खुद दाखिल करें, इसे कनीय अधिकारियों के भरोसे न छोड़ें। यदि 1 मई तक दाखिल रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई, तो 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

स्वतः संज्ञान से दर्ज इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोर्ट को बताया गया कि राज्य की जेलों में स्वीकृत पदों के मुकाबले 81 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। मैनपावर के इस भारी अभाव के कारण जेलों की सुरक्षा और 'मॉडल जेल मैनुअल' का पालन सुनिश्चित करना लगभग नामुमकिन हो गया है। हालांकि, सरकार की ओर से दलील दी गई कि असिस्टेंट जेलर, जेल वार्डन और मेडिकल नर्सिंग स्टाफ जैसे पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना मांगी गई है, लेकिन कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया।

झारखंड में संवैधानिक पदों पर लंबित नियुक्तियों पर हाईकोर्ट में सुनवाई: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को भरने के बारे में राज्य सरकार से 13 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। बुधवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री आवास पर चयन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नियुक्तियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। महाधिवक्ता ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल असम चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री लौटेंगे, बैठक में लिए गए निर्णयों और नियुक्ति की प्रगति से अदालत को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया जाएगा।

दूसरी ओर, प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि ये पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

सेहत कार्ड बनाने में जुटे 19,000 आशा वर्कर्सः डॉ बलबीर

चंडीगढ़, एजेंसी।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत राज्यभर में सेहत कार्ड बनाने के अभियान को तेज करने के लिए 19,000 से अधिक आशा वर्कर्स और 900 फैसिलिटेटर तैनात किए गए हैं। डॉ बलबीर ने कहा कि आशा वर्कर्स जमीनी स्तर पर इस योजना के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रत्येक वर्कर लगभग एक हजार लोगों और करीब 250 घरों को कवर करते हुए घर-घर जाकर योजना की जानकारी दे रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं और उन्हें सेवा केंद्रों व कॉमन सर्विस सेंटर तक नामांकन के लिए साथ भी ले जा रही हैं।

इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित हो रही है और नामांकन प्रक्रिया आसान बन रही है। उन्होने कहा कि पिछले 20 दिनों में ही आशा वर्कर्स की मदद से करीब 10 लाख नामांकन किए गए हैं, जिससे राज्य में स्वास्थ्य कवर का दायरा तेजी से बढ़ा है। इस अभियान को बनाए रखने के लिए आशा वर्कर्स को सफल नामांकन पर प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, जिससे जवाबदेही और निरंतर प्रयास सुनिश्चित हो रहे हैं।

योजना के उद्देश्य पर जोर देते हुए डॉ बलबीर ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण परेशान नहीं होगा। हमारी आशा वर्कर्स इस वादे को घर-घर तक पहुंचा रही हैं। यह केवल कागजों की योजना नहीं, बल्कि हर घर तक पहुंचाई जा रही गारंटी है। उन्होने कहा कि 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन लगभग 50,000 लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना , पटियाला और जालंधर जैसे जिले नामांकन में आगे हैं, जहां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब बजट 2026-27 में इस योजना के विस्तार के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में और अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। कैंप, सेवा केंद्र और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

सार समाचार

हरिद्वार में ई-रिक्शा पर प्रवर्तन अभियान, 50 वाहन जब्त

हरिद्वार,एजेंसी। उत्तराखंड में हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपद में ई-रिक्शा के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान का बुधवार को प्रथम दिन सघन कार्रवाई के साथ संपन्न हुआ। अभियान के दौरान बिना सत्यापन के संचालित 50 ई-रिक्शा को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ई-रिक्शा स्वामियों और चालकों का अनिवार्य सत्यापन कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में स्वामी और चालक दोनों का पुलिस सत्यापन शामिल है।

सत्यापन पूर्ण होने के बाद ई-रिक्शा पर रूट आधारित रंग-कोडित क्यूआर स्टिकर लगाए जाते हैं और चालकों को क्यूआर आधारित पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए

रायगढ़,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार को रायगढ़ प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजापारा स्थित जगन्नाथ मंदिर रायगढ़ पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इसके बाद वे उत्कल समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में 31 मार्च का दिन ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय समय-सीमा के अनुरूप सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों का आभार जताया।

32,801 करोड़ एसजीएसटी संग्रह, बिहार ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड

पटना,एजेंसी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)संग्रहण के मामले में वाणिज्यकर विभाग ने वर्ष 2024-25 के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया है। विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,801.35 करोड़ जीएसटी का संग्रहण किया गया,जो वर्ष 2024-25 से 11.67 फीसदी अधिक है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आईजीएसटी समायोजन के बाद राज्य का शुद्ध जीएसटी संग्रहण 32,077.22 करोड़ रहा, जो 9.20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी प्रावधिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में कुल संग्रहण वृद्धि दर के आधार पर चौथा स्थान प्राप्त किया है, जो कर प्रशासन में निरंतर सुधार और प्रभावी निगरानी का परिणाम है। आंकड़ो के अनुसार मार्च 2026 में एसजीएसटी एवं आईजीएसटी समायोजन सहित बिहार की वृद्धि दर 13 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 05प्रतिशत से काफी अधिक है।

रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण पूर्णः भजनलाल

जयपुर, एजेंसी।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर लिया गया है। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को शीघ्र अंतिम रूप देने और इसके लिए केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने परियोजना के विभिन्न घटकों में तेजी लाने और मिशन मोड पर काम करने के भी निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने परियोजना के पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए शेष कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए। साथ ही परियोजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की प्रगति के संबंध में मंत्री एवं मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित बैठक आयोजित की जाए। सतत पर्यवेक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से मासिक प्रगति रिपोर्ट ली जाए। उन्होंने परियोजना से प्रभावितों को मुआवजे के संबंध में विशेष निर्देश दिए।

उन्होंने बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बारैठा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ (जयपुर), खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) एवं ब्राह्मणी बैराज के कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

श्री शर्मा ने परियोजना के विभिन्न घटकों के अलाइनमेंट की जानकारी भी ली और परियोजना से संबंधित समस्त कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रामगढ़ बैराज एवं महलपुर बैराज के काफर डेम एवं डेनेज फीडर का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने नवनेरा बैराज से मेज एनीकट के डूब क्षेत्र तक फीडर निर्माण एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य, मेज एनीकट से गलवा बांध के डूब क्षेत्र तक फीडर ड्रेन, गलवा बांध से ईसरदा डूब क्षेत्र और बीसलपुर डूब क्षेत्र फीडर निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

हरियाणा की मंडियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, किसानों में नाराजगी

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन मंडियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर व्यापारियों और किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा बार-बार नए नियम लागू कर किसान और आढ़तियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फसल बेचने का समय सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक निर्धारित किया है, जिससे किसानों को भारी दिक्कत हो रही है।

किसान देर रात तक खेतों में कटाई करते हैं और फिर मंडियों में पहुंचते हैं, ऐसे में समय सीमा उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। इससे मंडियों और बाहर सड़कों पर ट्रैक्टर-ट्रालियों की लंबी कतारें लगने और जाम की स्थिति बनने की आशंका है। गर्ग ने सरकार से मांग की कि गेहूं और सरसों की खरीद के लिए बारदाना और लकड़ी के कैरेट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

उत्तराखंड के किसानों को मखाना की खेती करने के लिए दिया जाय प्रशिक्षणः जोशी

देहरादून,एजेंसी।

उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी से बुधवार को उनके शिविर कार्यालय में बिहार की एक निजी संस्था के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। हरिद्वार में मखाना की खेती करने जा रहे इन लोगों ने श्री जोशी को उदघाटन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने उन्हें राज्य के किसानों को इसका प्रशिक्षण देने का आग्रह कर दिया। प्रतिनिधि मंडल के मुखिया राजीव रंजन ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि उनकी संस्था लम्बे समय से मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में कार्य कर रही है।

उन्होंने उत्तराखण्ड में पहली बार जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मखाना की खेती के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए उनको आमंत्रित भी किया।

श्री जोशी ने इस पहल का स्वागत करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मखाना की खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही संस्थाओं के अनुभव का लाभ राज्य में लिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बिहार के उन क्षेत्रों का दौरा किया जाए, जहां मखाना का बेहतर उत्पादन हो रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन की जानकारी मिल सके।

बिहार में नर्सिंग शिक्षा का डिजिटल विस्तार, ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया शुरू

पटना,एजेंसी।

नर्सिंग संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन मान्यता प्रदान करने की सुविधा का शुभारंभ बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया। शास्त्रीनगर स्थित ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग संस्थानों के एनओसी और दूसरी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किए जाने से गुणवत्ता में सुधार एवं पारदर्शिता आएगी। श्री पांडेय ने कहा कि एक दशक पहले तक राज्य में नर्सिंग संस्थान नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल किए।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत तेजी से सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए। उन्होंने कहा कि आज बिहार में 656 नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग की अलग-अलग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हो रही है। इन संस्थानों में पढ़ाई के लिए 41 हजार 65 सीट स्वीकृत हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नर्सिंग संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए कारगर पहल करेगी, लेकिन संस्थानों को मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग की पढ़ाई में गुणवत्ता से किसी प्रकार समझौता नहीं होगा।

राज्य के नर्सिंग संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने वाले छात्र-छात्रा भविष्य में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित करेंगे। पांडेय ने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए आवेदन और एनओसी की सुविधा ऑनलाइन शुरू किए जाने से संस्थान प्रबंधन को दौड़-भाग से राहत मिलेगी।

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती 25 साल पुराने मामले में दोषी करार

दतिया,एजेंसी। मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपीएमएलए अदालत ने 25 साल पुराने बैंक के एफडी ब्याज घोटाले में आज दोषी ठहराया है। इसी क्रम में सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक राजेन्द्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मामले की सजा पर अभी अंतिम फैसला आना शेष है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मामला लगभग 25 साल पूर्व का भूमि विकास बैंक से जुड़ा है, जिसमें विधायक राजेन्द्र भारती ने अपनी मां के नाम 10.50 लाख रूपये की एफडी कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा था। राजेन्द्र भारती पर आरोप था कि उन्होंने तीन साल की एफडी को ज्यादा ब्याज के लालच में बैंक अध्यक्ष रहते हुये 2001 में फिर दस्तावेजों में गड़बड़ कर अवधि बढ़वा दी, ताकि ब्याज ज्यादा मिलता रहे।

हिमाचल विस में पंचायत आरक्षण अधिसूचना को लेकर हंगामा, भाजपा का बहिर्गमन

शिमला, एजेंसी।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को विपक्षी भाजपा सदस्यों ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण रोस्टर तय करने का अधिकार उपायुक्तों को देने वाली सरकार की अधिसूचना के विरोध में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की, जिसके चलते विधानसभा में हंगामा मच गया। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदस्यों को सूचित किया कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने यह मुद्दा उठाया है।

हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में सामान्य कार्यवाही स्थगित करने की कोई तात्कालिकता नहीं है और इस पर प्रश्नकाल के बाद विचार किया जाना चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने नियम 67 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की, जिससे हंगामा हुआ और कार्यवाही को सुबह 11:30 बजे तक के लिए संक्षिप्त रूप से स्थगित करना पड़ा। सदन की फिर बैठक होने के बाद, रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 31 जनवरी, 2025 से पहले होने वाले चुनावों में देरी करके पंचायती राज संस्थाओं को ₹संवैधानिक संकट₹ में धकेल दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अदालतों के निर्देशों के बावजूद, चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बहाने के रूप में 8 अक्टूबर को जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम की अधिसूचना का इस्तेमाल किया है। शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल, 2026 से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को 31 मई, 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण सूची और मतदाता सूची को 31 मार्च से पहले अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण अधिसूचना जारी करने के बजाय, सरकार ने रातोंरात जिला परिषदों को पांच प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार दे दिया, जिसे उन्होंने असंवैधानिक और राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन बताया। प्रस्ताव को खारिज करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और प्रश्नकाल में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी तुलना करते हुए कहा कि विपक्ष को याद रखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसे बड़े फैसले रातों-रात कैसे लिए थे।

नेगी ने तर्क दिया कि अद्यतन जनगणना आंकड़ों के अभाव में राज्य सरकार का यह कदम उचित था, क्योंकि अंतिम आंकड़े 2011 के थे। उन्होंने कहा कि अधिसूचना का उद्देश्य उन क्षेत्रों पर विचार करना था जहां जनसंख्या परिवर्तन (विशेष रूप से अनुसूचित जाति और ओबीसी बहुल क्षेत्रों में) के कारण आरक्षण में समायोजन की आवश्यकता थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने नगर निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रैल से पूर्व कराने का आदेश दिया था

भाजपा सरकार बहाने बनाकर टाल रही है निकाय एवं पंचायती चुनावः डोटासरा

जयपुर, एजेंसी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर जानबूझकर नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि बहाने बनाकर चुनाव टाले जा रहे हैं और वह न्यायालय के फैसलों की पालना नहीं कर रही है। डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गठन के ढाई वर्ष पूर्ण होने को है लेकिन बताने के लिये सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। प्रदेश में सभी नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं।

पंचायत राज संस्थाओं में 112 पंचायत समितियों को छोडक़र सभी पंचायत समितियों एवं समस्त ग्राम पंचायतों को कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कुछ स्थानों पर तो एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं हुये हैं, प्रशासक लगा दिये गये हैं। सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है, विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर समय-समय पर चुनाव आगे सरकाये गये। उन्होंने कहा कि अब ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलने का बहाना बनाकर चुनाव टाले जा रहे हैं, सरकार कानून को नहीं मान रही है, उच्च न्यायालय और उच्चत्तम न्यायालय के फैसलों की पालना नहीं कर रही है। भाजपा शासन में सभी नगर निकायों और पंचायतों में कार्य प्रशासक बिठा दिए गये जिससे स्थानीय स्तर पर होने वाला विकास भी ठप्प हो गया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने नगर निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रैल से पूर्व कराने का आदेश दिया था। ओबीसी आयोग को प्रतिनिधित्व के लिये तीन महीने में रिपार्ट देने के लिये गठन किया गया था ताकि जनाधार आदि देखकर एक समरी इनक्वाईरी सरकार से मौजूदा डेटा लेकर रिपोर्ट देनी थी और इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी प्रतिनिधत्व देकर सरकार को चुनाव करवाने थे, किन्तु जानबूझकर भाजपा सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बार-बार बढ़ाया, अब सितम्बर तक बढ़ा दिया गया है।

डोटासरा ने कहा कि आयोग गठन के शुरूआती छह महिने में तो संसाधन ही सरकार ने आयोग को नहीं दिये और अब जब रिपोर्ट तैयार है तो सरकार जानबूझकर रिपोर्ट नहीं ले रही है कि अगर रिपोर्ट आ गई तो चुनाव करवाने पड़ेगें, लेकिन भाजपा आज की परिस्थिति में जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। भाजपा को नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा सरकार की पोल खुल जायेगी, क्योंकि ढाई वर्ष में कुशासन से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की प्रतिनिधित्व के लिये रिपोर्ट नहीं आना सरकार की विफलता है, इसकी जवाबदेही सरकार की है, किन्तु सत्ता में बैठे हुये भाजपा नेता बेतुके तर्कों के आधार पर कांग्रेस नेताओं पर तंज कस रहे हैं।

बेअदबी मुद्दे पर दल खालसा ने अकाल तख्त जत्थेदार से हस्तक्षेप की मांग की

अमृतसर,एजेंसी।

सिख समुदाय में गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए कानून बनाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच दल खालसा ने बुधवार को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को पत्र लिखकर इस संवेदनशील मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सर्वसम्मति बनाने की अपील की है। दल खालसा ने यह भी घोषणा की कि वह पांच अप्रैल को 'बेअदबी, कानून और सिख पारंपरिक प्रतिक्रिया' विषय पर एक सेमिनार आयोजित करेगा। इस सेमिनार का उद्देश्य शब्द गुरू के सिद्धांत की सर्वोच्चता, पवित्रता और विशिष्टता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

दल खालसा के कार्यकारी अध्यक्ष परमजीत सिंह मंड ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेमिनार में कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी, जैसे बेअदबी की घटनाओं के पीछे कौन है? इसके पीछे क्या साजिश है? और इसके संभावित समाधान क्या हैं? उन्होंने बताया कि यह सेमिनार में वक्ता गुरू ग्रंथ साहिब की महिमा और शब्द गुरू की अवधारणा पर हो रहे कथित हमलों पर विचार रखेंगे। इस पहल का उद्देश्य सिख समुदाय को सतर्क और संगठित करना है, ताकि धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से समाधान निकाला जा सके।

इस बीच, पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है, जिसमें जगत जोत गुरू ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट , 2008 में सख्त संशोधन किए जाने की संभावना है।

यह कदम संत समाज की अपील पर उठाया गया है।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के स्पिनरों को दिखाना होगा दम

ईडन गार्डन्स केकेआर का गढ़ रहा है, जिसने 2008 से यहां खेले गए 95 मैचों में से 54 मैच जीते हैं।

कोलकाता,एजेंसी। अपने पहले मैच में हार का सामना करने वाली कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के गुरुवार को यहां होने वाले मैच में अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश करेंगी। इन दोनों टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है और ऐसे में गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है। केकेआर की टीम अपने स्पिनरों की फॉर्म में वापसी को लेकर उत्सुक होगा जबकि सनराइजर्स को भी अपने गेंदबाजी विभाग में काफी सुधार करना होगा।

यह मुकाबला तीन बार के चैंपियन केकेआर के लिए घरेलू मैदान पर होने वाले महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत भी है, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यहां सात दिन में तीन मैच और फिर 19 अप्रैल को एक और मैच खेलना है। विधानसभा चुनाव के कारण कोलकाता में लगभग एक महीने तक कोई मैच नहीं खेला जाएगा। केकेआर को इसके बाद चार मैच दूसरी टीमों के घरेलू मैदान पर खेलने हैं। उसका अपने घरेलू मैदान पर अगला मैच 16 मई को होगा और ऐसे में उसकी टीम इस चरण में लय हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

ईडन गार्डन्स केकेआर का गढ़ रहा है, जिसने 2008 से यहां खेले गए 95 मैचों में से 54 मैच जीते हैं। कुछ प्रमुख गेंदबाजों के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने से केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हुआ है। हर्षित राणा और आकाश दीप बाहर हो चुके हैं जबकि मथीशा पथिराना को अभी श्रीलंका क्रिकेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलना बाकी है। इसके अलावा 25.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए कैमरन ग्रीन फिलहाल केवल बल्लेबाज के रूप में उपलब्ध हैं।

केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण की कमजोरी मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में स्पष्ट तौर पर नजर आई जहां उसकी टीम 220 रन का बचाव नहीं कर सकी थी रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने केवल 72 गेंद पर 148 रन की साझेदारी की। इस मैच में केकेआर के मुख्य स्पिनरों सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को संघर्ष करना पड़ा था जो उनकी टीम के लिए चिंता का विषय होगा। ग्रीन ने पहले मैच में 10 गेंद पर 18 रन बनाए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी प्रबंधन के निर्देशों के कारण उन्होंने गेंदबाजी नहीं की।

ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने के कारण केकेआर उनकी जगह पर वेस्टइंडीज के रोवमैन पॉवेल को अंतिम एकादश में शामिल करने के बारे में सोच सकता है। पॉवेल ने टी20 विश्व कप में 147.52 के स्ट्राइक रेट से 149 रन बनाए। उन्होंने भारत के खिलाफ इसी मैदान पर सुपर आठ के मैच में 19 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए थे। केकेआर इस मैच के लिए टर्निंग विकेट तैयार करने के बारे में सोच रहा है लेकिन तब भी 200 का स्कोर औसत माना जाएगा केकेआर का कप्तान अजिंक्य रहाणे की अच्छी शुरुआत से हौसला बढ़ा होगा लेकिन उनका बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना चिंता का विषय होगा।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ रहाणे ने पावर प्ले में 18 गेंदों में 36 रन बनाए, लेकिन उसके बाद अगली 22 गेंदों में केवल 31 रन ही बना सके। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि 2023 से ही रहाणे पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं लेकिन इसके बाद उनका स्ट्राइक रेट तेजी से गिर जाता है।

आईपीएल 2026: रिजवी का तूफानी अर्धशतक, डीसी ने 6 विकेट से एलएसजी को हराया

उदय सिंह मीणा

लखनऊ। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। इस टीम ने बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीजन के पांचवें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। समीर रिजवी जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 47 गेंदों में 70 रन की नाबाद पारी खेली। बुधवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी एलएसजी 18.4 ओवरों में 141 रन पर सिमट गई। इस टीम को 19 के स्कोर पर कप्तान ऋषभ पंत (7) के रूप में झटका लगा। इसके बाद मिचेल मार्श ने एडेन मार्करम (11) के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी की।मार्श ने टीम के खाते में 35 रन का योगदान दिया।

टीम ने 71 के स्कोर तक अपना पांचवां विकेट खो दिया था। यहां से अब्दुल समद ने मुकुल चौधरी के साथ 34 रन और शाहबाज अहमद के साथ 33 रन की साझेदारी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

अब्दुल समद 25 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाहबाज अहमद ने नाबाद 15 रन जुटाए। मुकुल ने टीम के खाते में 14 रन जोड़े। विपक्षी खेमे से लुंगी एनगिडी और टी नटराज ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाले। 1 विकेट अक्षर पटेल के नाम रहा।इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 17.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। डीसी को पहली ही गेंद पर केएल राहुल (0) के रूप में झटका लगा। इसके बाद टीम ने 26 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे। इस बीच पथुम निसांका 1 रन, नितीश राणा 15 रन और कप्तान अक्षर पटेल खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए थे।यहां से समीर रिजवी ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 76 गेंदों में 119 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 17 गेंदें शेष रहते जीत दिला दी। रिजवी 47 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 70 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि स्टब्स ने 39 रन की नाबाद पारी खेली।

पोंटिंग ने मुझे आक्रामक खेलने को कहा था: कोनोली

मुल्लांपुर,एजेंसी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के जरिये आईपीएल में पदार्पण करने वाले पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली ने कहा कि मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने उन्हें आक्रामक खेलने की सलाह दी थी जबकि वह कप्तान श्रेयस अय्यर से भी सीखने को बेताब हैं। कोनोली ने 44 गेंद में नाबाद 72 रन बनाकर पंजाब को जीत दिलाई। कोनोली ने जियोस्टार से कहा, मैं सुबह उठा तो नर्वस था जिससे मुझे खुशी भी हुई। मुझे अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का इंतजार था। उन्होंने कहा, रिकी पोंटिंग ने मुझसे शांतचित्त होकर खेलने को कहा।

उन्होंने मुझसे आक्रामक बल्लेबाजी के लिये कहा। यह शानदार टीम प्रयास था। हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी जिससे चीजें आसान हो गई। कोनोली ने कहा, मैं श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी करके सीखना चाहता था। वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। मैने आस्ट्रेलिया ए और आस्ट्रेलिया के लिये उनके खिलाफ खेला है। मैं उनसे अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करूंगा।आस्ट्रेलिया के बाईस बरस के इस बल्लेबाज ने कहा कि आस्ट्रेलिया और पंजाब किंग्स के पूर्व खिलाड़ी शॉन मार्श उनके आदर्श हैं। उन्होंने कहा, मेरा चयन हुआ तो वह बहुत सुखद पल था। शॉन मार्श से मैने सबसे पहले बात की और उन्होंने मुझे सलाह दी। मैने वेस्टर्न आस्ट्रेलिया में उनके साथ काफी खेला है।

न्यूजीलैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

वेलिंग्टन,एजेंसी। कप्तान अमेलिया केर (नाबाद 179) की शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की महिला टीम ने बुधवार को दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दो गेंदें शेष रहते दो विकेट से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली हैं। 347 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड शुरुआत अच्छी नहीं हुई उसने 21 के स्कोर पर सुजी बेट्स (आठ) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी अमेलिया केर ने जॉर्जिया प्लिमर के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया।

दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 52 रन जोड़े। 16वें ओवर में कायला रेनेके ने जॉर्जिया प्लिमर (23) को आउट कर साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैडी ग्रीन (13) और ब्रूक हेलिडे (14) के विकेट झटक कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली। ऐसे संकट के समय इसाबेला गेज ने अमेलिया केर के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन भी बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान अमेलिया केर ने अपना शतक पूरा किया।

वहीं इसाबेला ने अर्धशतक बनाया। 38वें ओवर में एम क्लास ने इसाबेला गेज को आउट कर साझेदारी का अंत किया। इसाबेला गेज ने 48 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 68 रनों की पारी खेली। इजी शार्प (11), जेस केर (14) और रोजमेरी मेयर (दो) रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड ने 49.2 ओवरों में आठ विकेट पर 350 रन बनाकर मुकाबला दो विकेट से अपने नाम कर लिया। अमेलिया केर ने 139 गेंदों में 23 चौके और एक छक्का उड़ाते हुए नाबाद 179 रनों की मैच विजयी पारी खेली।

दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका ने तीन विकेट लिये। एम क्लास और कायला रेनेके को दो-दो विकेट मिले। सुने लूस ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 आवरों में छह विकेट पर 346 रनों का स्कोर बनाया। तेजमिन ब्रिट्स (नौ) का विकेट जल्द गिरने के बाद कप्तान लॉरा वुलफार्ट और अन्नेका बोश की जोड़ी ने पारी को संभाला तथा दूसरे विकेट लिए 132 रन जोड़ कर बड़े स्कोर की नींव रखी।

इराक, रिपब्लिक ऑफ कांगो ने क्वालिफ़ाई किया

मेक्सिको,एजेंसी। इराक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने मंगलवार को बोलीविया और जमैका पर प्लेऑफ जीत के बाद फीफा वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जगह पक्की कर ली। आयमान हुसैन ने दूसरे हाफ में गोल करके इराक को मोंटेरी में बोलीविया पर 2-1 से जीत दिलाई, जिससे टूर्नामेंट में वापसी का 40 साल का इंतज़ार खत्म हुआ। ल्यूटन टाउन के स्ट्राइकर अली अल-हमादी ने कॉर्नर से हेडर मारकर एशियाई टीम को आगे कर दिया, जिसके बाद मोइसेस पनियागुआ ने रामिरो वाका के डिफेंस को चीरते हुए पास के बाद 12 यार्ड से एक ज़ोरदार गोल करके बराबरी कर ली। हुसैन ने 53वें मिनट में अपनी टीम की बढ़त वापस ला दी, मार्को फार्जी के क्रॉस पर आठ गज की दूरी से पहली बार वॉली मारकर उन्होंने सही टाइमिंग से गोल बनाया। 1994 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही बोलीविया ने एक तनावपूर्ण मैच में आखिर में गोल करने की कोशिश की, लेकिन इराक ने 48 टीमों के वर्ल्ड कप स्पॉट में से आखिरी जगह पक्की करने के लिए मजबूती से बचाव किया। इराक के हेड कोच ग्राहम अर्नोल्ड ने कहा, मुझे खिलाड़ियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना है। उनके काम करने का तरीका, उन्होंने लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने की असली इराकी सोच दिखाई, इसीलिए हमने गेम जीता।

इराक, जो आखिरी बार 1986 में फुटबॉल के इस बड़े इवेंट में आया था, नॉर्वे, फ्रांस और सेनेगल के साथ ग्रुप आई में मुकाबला करेगा। इससे पहले, एक्सल टुआनज़ेबे ने एक्स्ट्रा-टाइम में गोल किया।

बिजनेस

प्रीमियम डीजल 1.50 रुपये महंगा

नई दिल्ली,एजेंसी। पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेज उछाल को देखते हुए देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बुधवार को अपने प्रीमियम डीजल की कीमत में 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी।

विमान ईंधन की कीमत में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि

नई दिल्ली,एजेंसी। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से विमान ईंधन के दाम में 100 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज 01 अप्रैल से दिल्ली में विमान ईंधन 2,07,341 रुपये प्रति किलोलीटर का हो गया है।

शेयर बाजारों में बढ़त के साथ हुई नये वित्त वर्ष की शुरुआत

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्की-50 सूचकांक भी 348 अंक यानी 1.56 प्रतिशत चढ़कर 22,679.40 अंक पर पहुंच गया।

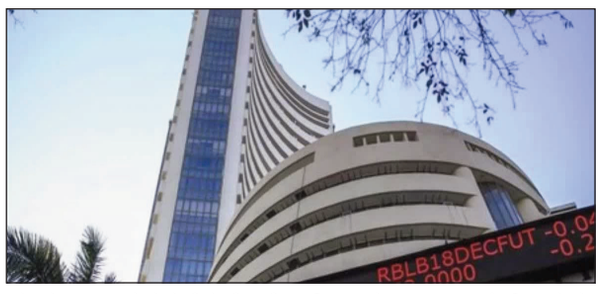

मुंबई,एजेंसी। पश्चिम एशिया में एक महीने से चल रहे संकट के सुलझने की उम्मीद में बुधवार को वित्त वर्ष के पहले दिन घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1,186.77 अंक (1.65 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 73,134.32 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्की-50 सूचकांक भी 348 अंक यानी 1.56 प्रतिशत चढ़कर 22,679.40 अंक पर पहुंच गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में ईरान युद्ध की समाप्ति का रोडमैप मिलने की उम्मीद में आज दुनिया भर में निवेशक लिवाल रहे और शेयर बाजारों में तेजी देखी गयी। चौतरफा लिवाली के बीच मझौली कंपनियों का निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.08 प्रतिशत और छोटी कंपनियों का स्मॉलकैप-100 सूचकांक 3.33 प्रतिशत उछल गया।

फार्मा और स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। सार्वजनिक बैंकों, धातु, आईटी, रसायन, रियलटी, ऑटो, निजी बैंकों और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों के सूचकांकों में ज्यादा तेजी रही। जिन 3,321 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,935 के शेयर हरे निशान में और 282 के लाल निशान में रहे। अन्य 104 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित बंद हुए।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 25 के शेयरों में तेजी रही। ट्रेंट का शेयर सात प्रतिशत उछल गया। इंडिगो में 6.01 फीसदी, अडानी पोर्ट्स में 5.47, बीईएल में 4.54, भारतीय स्टेट बैंक में 3.89 और इटरनल में 3.34 प्रतिशत की तेजी रही। एलएंडटी का शेयर 2.95 प्रतिशत, टाइटन का 2.81, एशियन पेंट्स का 2.75, एक्सिस बैंक का 2.66, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2.53, टीसीएस का 2.09 और इंफोसिस का दो प्रतिशत की बढ़त में रहा।

बजाज फाइनेंस का शेयर 1.97 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1.83, मारुति सुजुकी का 1.70, टाटा स्टील का 1.51, एचडीएफसी बैंक का 1.41, आईटीसी का 1.29, टेक महिंद्रा का 1.25, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1.02 और बजाज फिनसर्व का 0.99 प्रतिशत मजबूत हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर भी हरे निशान में रहे।

एनटीपीसी और सनफार्मा दोनों में 1.64 प्रतिशत की गिरावट रही। पावरग्रिड का शेयर भी 1.13 प्रतिशत लुढ़क गया। वैश्विक स्तर पर एशिया में जापान का निक्केई 5.24 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 2.04 फीसदी और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.46 फीसदी की बढ़त में रहा।

केंद्र ने एसईजेड यूनिट्स के लिए दरों में कटौती का ऐलान किया

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की पात्र इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में रियायती सीमा शुल्क दरों पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एकमुश्त राहत उपाय पेश किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, यह कदम केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई उस घोषणा के तहत उठाया गया है, जिसमें वैश्विक व्यापार में जारी व्यवधानों के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में विनिर्माण इकाइयों द्वारा सामना की जा रही चिंताओं को दूर करने का प्रावधान है।

इसे केंद्रीय बजट की घोषणा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत जारी छूट अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो विशेष आर्थिक इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र को भेजे गए निर्मित माल पर लागू होगी और 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी (अधिसूचना संख्या 11/2026-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2026)। इस राहत योजना के अंतर्गत पात्र विशेष आर्थिक इकाइयों के लिए रियायती दरों का निर्धारण करते समय, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है।

इस राहत योजना के तहत, जिन वस्तुओं पर वर्तमान में सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच में है अब 20 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगेगा। वहीं, जिन वस्तुओं पर वर्तमान में सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में है, उसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, 20 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 12.5 प्रतिशत; 12.5 और 15 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, 10 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस राहत योजना के तहत लाभ का दावा करने वाली ऐसी इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं में इनपुट की तुलना में न्यूनतम 20 प्रतिशत का मूल्यवर्धन होना चाहिए।

विशेष आर्थिक इकाइयों द्वारा निर्यात पर जोर जारी रहेगा। पात्र एसईजेड इकाइयों द्वारा रियायती दरों पर की गई डीटीए बिक्री, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष के उच्चतम वार्षिक एफओबी निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह राहत योजना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्वचालित प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी और इस राहत योजना के तहत डीटीए क्लीयरेंस के लिए एंट्री बिलों का मूल्यांकन फेसलेस असेसमेंट प्रणाली के तहत किया जाएगा

भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2026 में 30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद: रिपोर्ट

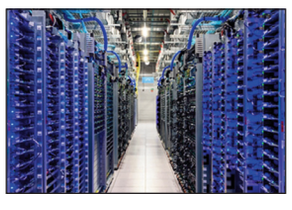

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2026 में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह मजबूत मांग और इस सेक्टर में निवेशकों की रुचि बने रहना है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। सीबीआरई के विश्लेषण के अनुसार, इस वर्ष लगभग 500 मेगावाट के नई डेटा सेंटर क्षमता जोड़े जाने का अनुमान है, जो 2025 में जोड़ी गई रिकॉर्ड 440 मेगावाट की क्षमता से अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक घरेलू डेटा सेंटर की कुल क्षमता लगभग 1,700 मेगावाट थी। इस सेक्टर ने नई पूंजी भी आकर्षित की है और 2025 में 56.4 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं, जिससे कुल निवेश प्रतिबद्धताएं 126 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। इन प्रतिबद्धताओं में इस वर्ष लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह राशि संभावित रूप से 180 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है।

सीबीआरई के अध्यक्ष और सीईओ अंशुमन मैगजीन ने कहा, ₹भारत में डेटा सेंटर की कहानी अब संभावनाओं के बारे में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन के बारे में है।₹ उन्होंने आगे कहा कि विकास को गति देने में विदेशी पूंजी की प्रमुख भूमिका बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य निवेश में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

हालांकि कम लेटेंसी, 5जी रोलआउट और डेटा स्थानीयकरण की बढ़ती मांग के कारण अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, पटना और भोपाल सहित टियर-II शहरों में भी गतिविधि तेजी से फैल रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुंबई सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है - भारत के कुल चालू डेटा सेंटरों में से 50 प्रतिशत से अधिक मुंबई में स्थित हैं।

मुंबई, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु मिलकर कुल क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत योगदान करते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग से बढ़ती मांग के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे ऑपरेटर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में यात्री वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री

नई दिल्ली,एजेंसी। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में करीब 47 लाख यात्री वाहनों की बिक्री के साथ नया रिकॉर्ड बना है। यात्री वाहनों में कार, उपयोगी वाहन और वैन शामिल हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश चंद्रा ने बुधवार को एक बयान में बताया कि गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में यात्री वाहन उद्योग की सालाना बिक्री करीब 47 लाख पर पहुंची है जो एक साल पहले की तुलना में आठ फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि दूसरी छमाही में उद्योग ने बिक्री में दहाई अंक की वृद्धि दर्ज की। इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नयी पीढ़ी के बदलावों और बेहतरीन त्योहारी सीजन की अहम भूमिका रही।

चंद्रा ने, जो वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के अध्यक्ष भी हैं, कहा कि स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दो लाख इकाई को पार कर गयी। साथ ही सीएनजी पर चलने वाले वाहनों की बिक्री में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यात्री वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि उसकी कुल बिक्री लगातार तीसरे साल 20 लाख इकाई के पार रही है। बीते वित्त वर्ष में उसने 24,22,713 वाहन बेचे जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इस दौरान घरेलू बिक्री रिकॉर्ड 18,61,704 इकाई पर और निर्यात 4,47,774 इकाई के नये उच्चतम स्तर पर रहा।

मार्च में कंपनी ने घरेलू बाजार में कुल 1,69,428 वाहन बेचे जबकि 47,040 वाहनों का निर्यात किया। साथ ही उसने दूसरी विनिर्माण कंपनी के भी 8,783 वाहन बेचे। इस प्रकार उसकी कुल मासिक बिक्री 16.72 प्रतिशत उछलकर 2,25,251 इकाई रही। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने बताया कि मार्च में उसकी घरेलू बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 66,192 इकाई पर और निर्यात 204 फीसदी बढ़कर 779 इकाई पर पहुंच गयी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कंपनी की बिक्री 77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9,494 इकाई दर्ज की गयी।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने घरेलू बाजार में 6,31,387 वाहन बेचे और इसमें 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। निर्यात 281 फीसदी बढ़कर 10,200 इकाई रही। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 43 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 92,120 इकाई दर्ज की गयी। चंद्रा ने कहा कि कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष और चौथी तिमाही में बिक्री के नये रिकॉर्ड बनाये। वाहन पंजीकरण के आधार पर कंपनी वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की दूसरी सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता बन गयी है।

दक्षिण अफ्रीका में कंपनी के दोबारा प्रवेश करने से निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी घरेलू बाजार में मासिक और तिमाही बिक्री का नया कीर्तिमान कायम किया है। मार्च में उसकी घरेलू बिक्री 55,064 इकाई रही जो एक साल पहले के मुकाबले 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। कंपनी ने महीने के दौरान 13,940 इकाई का निर्यात किया। इस प्रकार कुल बिक्री 69,004 इकाई रही।

तिमाही में उसने कुल 2,08,275 वाहन बेचे जो 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। इसमें घरेलू बिक्री 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1,66,578 इकाई और निर्यात 9.4 प्रतिशत बढ़कर 41,697 इकाई रहा। रेनो इंडिया की बिक्री मार्च में 77 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के साथ 5,046 इकाई पर पहुंच गयी। मार्च की बिक्री में 63 प्रतिशत योगदान कंपनी की काइगर और ट्राइबर कारों का रहा।

पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने 42,018 वाहन बेचे जो 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। फोर्स मोटर्स की बिक्री मार्च में 14 प्रतिशत बढ़कर 4,126 इकाई और पूरे वित्त वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 36,536 इकाई पर रही।

'सुबह सही तो सब सही', सामंथा रूथ प्रभु ने शेयर किया अपना 'पावर मॉर्निंग' रूटीन

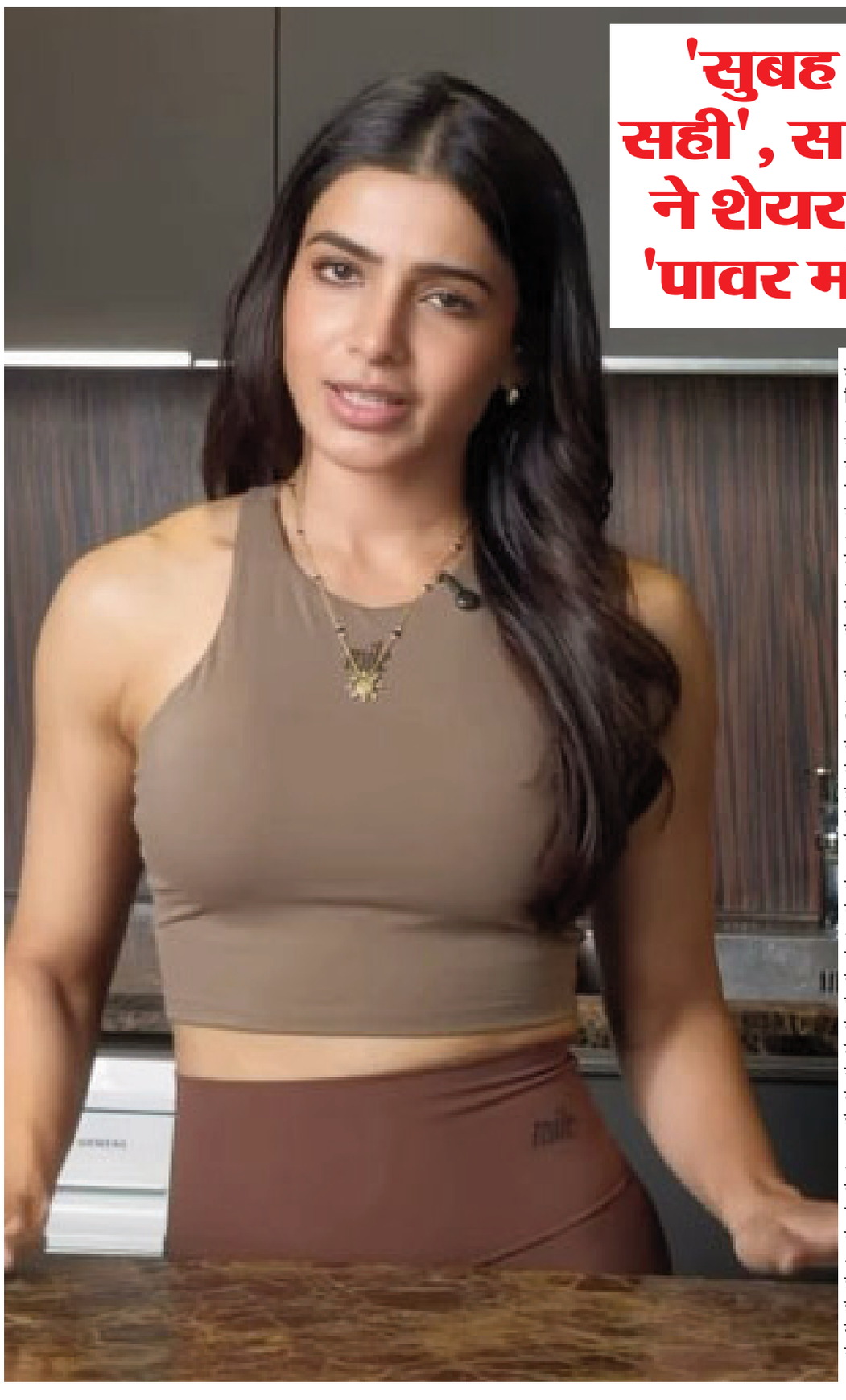

नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस, स्किन और मानसिक शांति के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसको लेकर अब अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने अपनी 'पावर मॉर्निंग' रूटीन साझा की है। उन्होंने बताया कि कैसे सही तरीके से दिन की शुरुआत करने से न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने कई तरह की मॉर्निंग रूटीन आजमाई हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें एक ऐसा आसान तरीका मिला जो उनके लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ। उन्होंने इसे 'पावर मॉर्निंग' नाम दिया।

सामंथा ने कहा, ''अगर सुबह सही तरीके से शुरू होती है, तो पूरा दिन सबकुछ सही होता है। ऊर्जा अपने आप बेहतर हो जाती है।''वीडियो में सामंथा ने कहती है, ''कई बार लोग सब कुछ सही करने के बावजूद भी पेट की चर्बी कम नहीं कर पाते, स्किन की समस्याएं बनी रहती हैं या सुबह उठते समय चेहरा सूजा हुआ लगता है। इसकी एक बड़ी वजह गलत मॉर्निंग रूटीन हो सकती है। इसलिए लोगों को अपनी सुबह की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है।''

सामंथा ने खासतौर पर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ''सुबह उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर ज्यादा होता है, जो सामान्य है। लेकिन अगर हम उठते ही फोन, न्यूज या काम देखने लगते हैं, तो यह स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इससे दिनभर ध्यान कम रहता है।''अपनी रूटीन को विस्तार से बताते हुए सामंथा ने सबसे पहला नियम बताया कि उठने के बाद एक घंटे तक फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ मिनट शांति में बैठकर गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि आप सुरक्षित हैं, जिससे शरीर बेहतर तरीके से काम करता है और हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा, ''उठने के 10 मिनट के अंदर चेहरे पर धूप लेना फायदेमंद होता है। साथ ही एक हेल्दी ड्रिंक और संतुलित नाश्ता ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है।''इस वीडियो के कैप्शन में सामंथा ने लिखा, 'इस रूटीन को बनाने में मुझे कई साल लगे, लेकिन इसका असर मेरी जिंदगी पर गहराई से पड़ा है। आप 21 दिनों तक इस रूटीन को लगातार अपनाएं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को कितना बदल सकते हैं।'

सोना मोहपात्रा ने उत्कल दिवस पर अपनी जड़ों को किया नमन

मुंबई। मशहूर गायिका सोना मोहपात्रा ने अपनी दमदार आवाज से दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी हैं। गायिका ने उत्कल दिवस के अवसर पर ओडिशा में अपनी जड़ों को दिल से नमन किया और राज्य की समृद्ध कलात्मक विरासत को उजागर किया।

सोना ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी कला की जड़ों का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, 'यह है रघुराजपुर, मेरे राज्य ओडिशा का एक कलाकार गांव। यहां कला को सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती है। मैं इसी पवित्र धरती से आई हूं, जहां कला कोई रोजगार नहीं बल्कि एक प्रार्थना और भक्ति है।'

सोना ने बताया कि रघुराजपुरा गांव में हर घर एक छोटी कार्यशाला जैसा है। यहां कई कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। हर कलाकार सदियों पुरानी परंपराओं का संरक्षक हैं। पतचित्रा, मूर्तिकला और अन्य पारंपरिक कलाओं को ये लोग जीवित रखे हुए हैं।उत्कल दिवस (ओडिशा स्थापना दिवस) के मौके पर सोना ने अपनी जड़ों को नमन किया। उन्होंने लिखा, 'ओडिशा की इस धरती पर कला में बेजोड़ कौशल, विस्तार, अनुशासन और आत्मा दिखती है। यहां हम सिर्फ सुंदरता को नहीं अपनाते, बल्कि खुद सुंदरता बन जाते हैं।'

सोना ने इस पोस्ट के साथ एक खास गीत नीलमणि भी ऐड किया। गायिका ने गीत के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा, 'इस गीत को मैंने और रामसंपथ ने मिलकर रिलीज किया। यह सांबलपुरी बोली में हैं और कृष्ण भगवान के प्रति एक भक्ति गीत है। रघुराजपुर, ओडिशा के पुरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध विरासत शिल्प ग्राम है, जहां के हर घर में कलाकार निवास करते हैं। यह मुख्य रूप से पारंपरिक पट्टाचित्र चित्रकारी, सनकी, मूर्तियां और अन्य पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। कई पीढ़ियों से ये कलाकार अपनी कला को संभालते आ रहे हैं।यह गांव ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती, प्रसिद्ध 'गोतिपुआ' नृत्य मंडलों का केंद्र भी है। यह पुरी-भुवनेश्वर राजमार्ग पर चंदनपुर के पास स्थित है, जो पुरी से लगभग 14 किमी दूर है।

ऑटो से चलना संघर्ष नहीं, जिंदगी है : जीशु सेनगुप्ता

मुंबई। मायानगरी मुंबई को 'सपनों का शहर' कहा जाता है, जहां हर साल हजारों लोग सुनहरे भविष्य और सफलता की चाह में कदम रखते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो पहले अपने गृह राज्य में ही अनुभव और हुनर हासिल करते हैं, ताकि मुंबई के कड़े संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सकें। लोकप्रिय अभिनेता जीशु सेनगुप्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अभिनेता ने हाल ही में आईएएनएस के साथ खास बातचीत में बताया कि बॉलीवुड में आना उन्हें उतना मुश्किल नहीं लगा, जितना लोग सोचते हैं।

दरअसल, अभिनेता बंगाली सिनेमा का जाना-माना नाम है और उन्होंने कई अच्छे निर्देशकों के साथ काम किया है। अभिनेता ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि पहले वे कई बंगाली फिल्ममेकर्स के साथ काम कर चुके थे, जिस वजह से बॉलीवुड में उन्हें उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने कहा, 'मैंने प्रदीप सरकार, अनुराग बसु, सुजॉय घोष और सुजीत सरकार जैसे जाने-माने बंगाली डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। वे बॉलीवुड में भी काफी मशहूर हैं। ये लोग जानते थे कि मैं किस तरह का काम करता हूं। इसलिए यहां मेरे लिए चीजें काफी आसान रहीं।'

जीशु ने कहा कि वे आम अनुभवों को संघर्ष नहीं बल्कि, जिंदगी का सामान्य हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा, 'यह आपके नजरिए की बात है। मैं ऑटो से जाने को संघर्ष नहीं समझता। लाखों-करोड़ों लोग रोज इसी तरह सफर करते हैं। मैं चाहूं तो इसे घुमा-फिराकर कह सकता हूं कि मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मैं इसे उस तरह नहीं देखता। इसलिए मेरे हिसाब से मैंने कोई संघर्ष नहीं किया है।'

अभिनेता ने यह भी बताया कि उनके मैनेजर ने उन्हें बॉलीवुड में बड़ा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, 'मेरी टीम ने यहां तक आने पर मुझे बहुत मजबूर किया था, खासकर मेरी मैनेजर ने। मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और बंगाल के बाहर भी काम शुरू करना चाहिए। शुरू में मैं इसके लिए ज्यादा उत्सुक नहीं था, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश था। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैंने यह कदम उठाया।'

विदेश

बांग्लादेश: खसरे से 44 की मौत

ढाका। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और बीते 24 घंटों में संदिग्ध मामलों और जटिलताओं से चार बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस साल मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 44 हो गई है, जिससे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। राजशाही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रवक्ता शंकर के. बिस्वास के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दो बच्चों की मौत (संदिग्ध मामला) खसरे से हुई।

इराक में अमेरिकी पत्रकार का अपहरण

बगदाद। इराक के बगदाद में एक अमेरिकी पत्रकार को अपहृत कर लिया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने पुष्टि की है कि इसमें ईरान-समर्थित मिलिशिया समूह का संदेह है, जिससे इस क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता बढ़ गई है।

ईरान में क्रूर शासन के खिलाफ हमारे संघर्ष की दहाड़ पूरी दुनिया सुन रही : नेतन्याहू

तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, इजरायल के नागरिकों, इस स्वतंत्रता के पर्व की पूर्व संध्या पर इजरायल पहले से कहीं अधिक मजबूत है। पूरी दुनिया ईरान की दुष्ट सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी शेर जैसी गर्जना सुन रही है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हमने बेहद बड़ी व विशाल उपलब्धियां हासिल की हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसकी एक पीड़ादायक कीमत भी है। अभी कल ही, हमने अपने चार सर्वश्रेष्ठ बेटों को खो दिया। इजरायल के नागरिकों की ओर से और मेरी व मेरी पत्नी सारा की ओर से मैं शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। हम सभी प्रेम के साथ उन परिवारों को गले लगाते हैं जिन्होंने अपना सबसे अनमोल सदस्य खो दिया है और हम अपने वीर घायल साथियों को भी प्रेम से गले लगाते हैं। हम एक ही लोग हैं, एक साझा नियति की डोर से बंधे हुए, अपने अस्तित्व और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए साथ हैं।

अमेरिका के साथ हमारे संयुक्त अभियान के एक महीने पूरे होने पर हम व्यवस्थित रूप से उस आतंकी शासन को कुचल रहे हैं जिसने दशकों तक यह नारा लगाया: "अमेरिका की मौत, इजरायल की मौत।" यह सच है कि हर पीढ़ी में वे हमें नष्ट करने के लिए उठ खड़े होते हैं और इस पीढ़ी में आयतुल्लाओं के शासन ने हमें समाप्त करने, मध्य पूर्व पर कब्ज़ा करने और पूरी दुनिया को धमकाने का बड़ा प्रयास किया। उसने इन घातक इरादों को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु कार्यक्रमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया, हमारे आसपास आतंकवादी संगठनों को धन और हथियार दिए और उस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को झेलते हुए आगे बढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्षों में इस सब पर ईरान को लगभग एक ट्रिलियन डॉलर का खर्च आया है। अब यह कहा जा सकता है कि वह पैसा व्यर्थ चला गया।

ईरान से वसूली गई कीमत केवल धन तक सीमित नहीं थी। आने वाले पासओवर (मुक्ति पर्व) की भावना में 'मोचन युद्ध' की शुरुआत से ही, हमने 'बुराई के धुरी' पर दस विपत्तियां डाली हैं। गाज़ा में हमास पर प्रहार, लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर प्रहार, सीरिया में असद पर प्रहार, यहूदिया और समारिया में आतंकी संगठनों पर प्रहार, यमन में हूतियों पर प्रहार, और ईरान पर पांच और प्रहार- उनके परमाणु कार्यक्रम पर प्रहार, उनकी मिसाइलों पर प्रहार, शासन की बुनियादी संरचना पर प्रहार, दमनकारी ताकतों पर प्रहार, और "पहिलोठों की विपत्ति", या हमारे मामले में, शीर्ष नेतृत्व पर प्रहार।

तानाशाह खामेनेई से लेकर परमाणु वैज्ञानिकों तक और रिवोल्यूशनरी गार्ड व बसीज के कुख्यात हत्यारों तक, नसरल्लाह, हनियेह, डेइफ़, सिनवार और कई अन्य तक। मिस्र की दस विपत्तियों के बाद भी फ़िरऔन ने इजरायल के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और हम सभी जानते हैं उसका अंत क्या हुआ। यही स्थिति ईरानी 'बुराई के धुरी' के खिलाफ अभियान में भी है। यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी यह कहा जा सकता है कि हमारे दुश्मनों पर आई इन दस विपत्तियों के मुकाबले, हमने 'राइजिंग लॉयन' और 'रोअरिंग लॉयन' अभियानों तथा पूरे 'मोचन युद्ध' में दस बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

'दुनिया से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील'

जिनेवा। बलूच वीमेन फोरम (बीडब्ल्यूएफ) की सेंट्रल ऑर्गनाइजर शाली बलूच ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र के दौरान बलूचिस्तान भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। इनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा लोगों को जबरदस्ती गायब करना और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के हत्याएं करना शामिल है।

गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार बलूच नागरिकों को आतंकवादी बताकर उन्हें निशाना बना रहा है और उनकी हत्याएं कर रहा है।वर्चुअली इस सत्र को संबोधित करते हुए शाली ने कहा कि पाकिस्तान के शासन के अधीन स्थित बलूचिस्तान गंभीर मानवाधिकार हनन का सामना कर रहा है, जिसमें हाल के दिनों में बलूच महिलाओं और बच्चों पर सीधे हमले भी शामिल हैं। जबरन गायब किए जाने से लेकर गैर-न्यायिक हत्याओं तक, देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां (सेना और अर्धसैनिक बल भी शामिल) इन सबमें लिप्त हैं।

उन्होंने बताया कि अकेले 2025 में ही जबरन गायब किए जाने के लगभग 1355 मामले सामने आए हैं, जिनमें 18 महिलाएं और 225 हत्याएं शामिल हैं।बलूच कार्यकर्ता ने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने में लगा हुआ है, और उन्हें आतंकवादी करार दे रहा है। स्थानीय लोगों की गवाहियां सरकार के दावों से बिल्कुल अलग हैं।शाली ने वैश्विक समुदाय से अपील की कि वे बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के सभी उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराएं, और नागरिकों के जबरन गायब होने तथा उनकी हत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग की।

जुलाई चार्टर कुछ और नहीं अंतरिम सरकार का दिया धोखा: बांग्लादेश के गृह मंत्री

ढाका। बांग्लादेश में जुलाई चार्टर को लेकर राजनीति जारी है। देश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान जारी 'जुलाई नेशनल चार्टर (कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म) इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर, 2025' की कड़ी निंदा की और इसे 'धोखे का कभी न खत्म होने वाला डॉक्यूमेंट' और 'नेशनल फ्रॉड' बताया है। स्थानीय मीडिया ने उनके बयान को प्रमुखता से छापा है। विपक्ष के नेता और जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने संसद में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ₹ये निर्देश कानूनी तौर पर वैध नहीं हैं।'

बांग्लादेशी डेली ढाका ट्रिब्यून ने अहमद के हवाले से कहा, 'इस आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह शुरू से ही गैरकानूनी है।'उन्होंने अंतरिम सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट पेश करने से पहले अलग-अलग सियासी दलों की ओर से जमा किए गए 'असहमति के नोट्स' को शामिल नहीं किया गया।

अहमद ने आगे कहा, 'यह अंतरिम सरकार की लगातार धोखा देने की प्रवृत्ति दर्शाती है। सियासी पार्टियों की अलग राय के बावजूद इसे जनता के सामने पेश करना देश के साथ धोखा है।'उन्होंने पिछली अंतरिम सरकार की सलाह पर जुलाई चार्टर पर जारी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वैधता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार 7 अप्रैल, 1973 के बाद खत्म हो गया था।

जन्मसिद्ध नागरिकता मामले में अदालत में उपस्थित होंगे डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जन्मसिद्ध नागरिकता पर सुनवाई के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने की योजना बना रहे हैं। शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर उनके कार्यकारी आदेश को चुनौती देने वाले एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले की सुनवाई करने जा रही है। ट्रंप ने अदालत में उपस्थित होने के बारे में पूछे जाने पर कहा, "मुझे लगता है हाँ, मैं जाऊँगा क्योंकि मैं इस तर्क को लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ।"

यह मामला ट्रंप के उस प्रयास पर केंद्रित है, जिसमें वे गैर-नागरिक माता-पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं- जो 14वें संशोधन पर आधारित एक लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक व्याख्या है।

ट्रंप ने अपने तर्क को ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता को गृहयुद्ध के बाद के दौर से जोड़ा। उन्होंने कहा, "यह दासों के बारे में था और यह दासों के बच्चों व उनके संरक्षण से संबंधित था।"उन्होंने तर्क दिया कि इस नीति का वर्तमान उपयोग उसके मूल उद्देश्य से भटक गया है। ट्रंप ने कहा, "यह करोड़पतियों और अरबपतियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए नहीं था।"मौजूदा व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, "यह सबसे अजीब चीज़ है जो मैंने कभी देखी है। वर्षों से इसे कानूनी लोगों द्वारा बहुत खराब तरीके से संभाला गया है।"

ट्रंप ने इस नीति के दुरुपयोग की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "हम ऐसे लोगों को देख रहे हैंजिन्हें कहा जाता है, बधाई हो, आपका पूरा परिवार अब अमेरिका का नागरिक बनने जा रहा है।"राष्ट्रपति ने अपने कानूनी पक्ष पर भरोसा जताया लेकिन न्यायिक फैसलों को लेकर चिंता भी व्यक्त की। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "आपके पास सबसे मजबूत मामला हो सकता हैफिर भी वे आपके खिलाफ फैसला दे सकते हैं।"इसके विपरीत, उन्होंने रिपब्लिकन द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के बारे में कहा कि वे अक्सर "यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितने सम्मानित हैं" और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं।